

कृषक जगत

राष्ट्रीय कृषि अखबार

भोपाल-जयपुर-रायपुर

ISSN -0970-8650

संस्थापित 1946 भोपाल, प्रकाशन - सोमवार, 6 अक्टूबर 2025 वर्ष-80 अंक - 6 मूल्य-रु. 12/- कुल पृष्ठ-16 www.krishakjagat.org पृष्ठ- 1

कृषक जगत न्यूज़ वेबसाइट पर जाने के लिए QR कोड स्कैन करें



फव्वारा सिंचाई: लाभकारी सूक्ष्म सिंचाई पद्धति

कृषक जगत की संचालक डॉ. साधना गंगराड़े सम्मानित



मध्य प्रदेश के राज्यपाल महामहिम श्री मंगूभाई पटेल ने गत दिनों हिन्दी भवन भोपाल में आयोजित एक गरिमामय समारोह में कृषक जगत की संचालक एवं हिन्दी लेखिका संघ की प्रांताध्यक्ष डॉ. साधना गंगराड़े को हिन्दी सेवी पुरस्कार से शॉल, श्रीफल एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। मध्य प्रदेश राष्ट्रभाषा प्रचार समिति द्वारा आयोजित गरिमामय कार्यक्रम में समिति के उपाध्यक्षद्वय श्री रघुनंदन शर्मा एवं श्रीमती रंजना अरगड़े, राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री मनोज श्रीवास्तव एवं वरिष्ठ साहित्यकार डॉ. महेश सक्सेना, सप्रे संग्रहालय के संचालक श्री विजय दत्त श्रीधर सहित राष्ट्रभाषा प्रेमी एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

किसानों को मिला दशहरे का तोहफा

गेहूं का समर्थन मूल्य 160 रु. बढ़कर 2585 रु. प्रति क्विंटल हुआ

रबी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित

(नई दिल्ली कार्यालय)

नई दिल्ली। दशहरे से ठीक पहले मोदी सरकार ने किसानों के लिए ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 'राष्ट्रीय दलहन मिशन' को मंजूरी दी गई है और साथ ही रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में बढ़ोतरी की गई है। केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि ये फैसले किसानों की आय बढ़ाने, दालों में आत्मनिर्भरता लाने और देश की खाद्य व पोषण सुरक्षा मजबूत करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होंगे। बुवाई से पूर्व एमएसपी की जानकारी होने पर किसान को फसल चयन करने में आसानी होती है। क्योंकि उसे पता होता है कि कौन सी फसल कितने रुपए क्विंटल बिकेगी। केन्द्र सरकार ने वर्ष 2025-26 में रबी फसलों का एमएसपी बढ़ाया है। इससे विपणन सीजन 2026-27 में खरीदी की जाएगी।

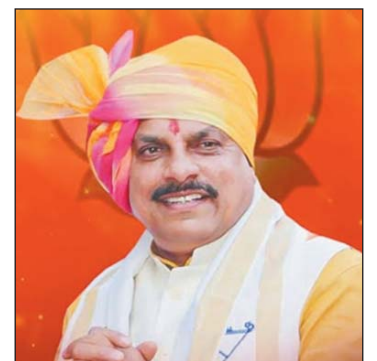


एमएसपी बढ़ाने का फैसला
केंद्रीय मंत्री के अनुसार, गेहूं समेत रबी फसलों की एमएसपी में उल्लेखनीय वृद्धि करते हुए लागत पर 109 प्रतिशत तक लाभ किसानों को मिलेगा। श्री चौहान ने कहा- कैबिनेट के इन ऐतिहासिक फैसलों से किसानों की आमदनी, (शेष पृष्ठ 2 पर)



किसानों के कल्याण के लिए केन्द्र और राज्य सरकार प्रतिबद्ध: डॉ. यादव

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रीमंडल द्वारा रबी फसलों की एमएसपी में वृद्धि को स्वीकृति देने का स्वागत किया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि केन्द्रीय मंत्रीमंडल ने विपणन सत्र 2026-27 के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि कर अन्नदाताओं का हित संवर्धन किया है। इस निर्णय से मध्यप्रदेश के किसान बंधु भी बड़े पैमाने पर लाभान्वित होंगे। किसानों के कल्याण के लिए केन्द्र और राज्य सरकार दोनों ही प्रतिबद्ध हैं।



'दलहन आत्मनिर्भरता मिशन' की स्वीकृति का निर्णय भी किसान हित की दृष्टि से ऐतिहासिक है। वर्ष 2025-26 से 2030-31 तक दाल उत्पादन 350 लाख टन तक पहुंचाने का लक्ष्य तय किया गया है। इसके लिए 11 हजार 440 करोड़ रुपए का निवेश भी किया जाएगा।

इफको का है वादा, लागत कम उत्पादन ज्यादा

500 मिली बोतल मात्र रु. 225/- में

इफको नैनो उर्वरकों की प्रत्येक बोतल पर रु. 10000/- (अधिकतम 2 लाख) का आकर्षक दृष्टान्त बीमा मुफ्त*

फसलों की भरपूर पैदावार के लिए इफको के उत्पादों की उत्कृष्ट श्रृंखला

IFFCO

पूरण: सहकारी स्वामित्व
Wholly owned by Cooperatives

आत्मनिर्भर भारत आत्मनिर्भर कृषि

500 मिली बोतल मात्र रु. 400/- में

इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड राज्य कार्यालय- ब्लॉक 2, तृतीय तल, पर्यावास भवन अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.)

अधिक जानकारी हेतु : www.nanourea.in - www.nanodap.in साहक सेवा हेल्पलाइन नंबर (टोल फ्री): 1800 103 1967 ifco.coop ifco_coop ifco_PR ifco

किसानों और इंडस्ट्री की मांगों के अनुरूप ही रिसर्च का मतलब : श्री चौहान

केंद्रीय कृषि मंत्री ने गन्ना अर्थव्यवस्था पर राष्ट्रीय परामर्श सत्र को किया संबोधित



नई दिल्ली/भोपाल (कृषक जगत)। केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कृषि अनुसंधान तभी सार्थक है जब उसका सीधा फायदा किसानों को मिले। उन्होंने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) से गन्ना अनुसंधान के लिए अलग टीम गठित करने को कहा, जो गन्ने की नीतियों और किसानों की व्यावहारिक समस्याओं पर काम करेगी।

पूसा परिसर में आयोजित 'गन्ना अर्थव्यवस्था पर राष्ट्रीय परामर्श सत्र' को भोपाल से वरुचुअल संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि गन्ने की नई किस्मों में चीनी की मात्रा तो बेहतर है, लेकिन रोग बढ़ी चुनौती हैं। मोनोकॉपिंग से मिट्टी की

उर्वरता और उत्पादन प्रभावित होता है, इसलिए इंटरक्रॉपिंग और रोग-प्रतिरोधी किस्मों पर रिसर्च जरूरी है।

उन्होंने लागत घटाने, उत्पादन बढ़ाने, मैकेनाइजेशन और पानी की बचत पर जोर देते हुए कहा कि 'पर ड्रॉप-मोर क्रॉप' सोच को आधार बनाना होगा। श्री चौहान ने कहा कि एथेनॉल, मोलासेस और अन्य बायो-प्रोडक्ट्स से किसानों की आमदनी बढ़ाई जा सकती है।

केंद्रीय मंत्री ने चीनी मिलों से समय पर भुगतान सुनिश्चित करने और किसानों की कैपेसिटी बिल्डिंग पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता बताई। साथ ही कहा कि प्राकृतिक खेती और बायो-प्रोडक्ट्स को भी उर्वरक संकट के समाधान के रूप में देखा जा सकता है।

कार्यक्रम में आईसीएआर के महानिदेशक डॉ. एम.एल. जाट सहित अनेक विशेषज्ञों ने अपने विचार रखे।

तीनों राज्यों के 27 लाख किसानों को मिली 540 करोड़ पीएम सम्मान निधि की राशि

केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त जारी करने की घोषणा की। यह किस्त विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड के उन किसानों के लिए है, जो हाल ही में आई बाढ़ और भूस्खलन से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं।



हिमाचल प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड के कृषि मंत्री, सांसद, विधायक और वरिष्ठ अधिकारी, साथ ही किसान समूहों के प्रतिनिधि भी इस कार्यक्रम में वरुचुअल माध्यम से शामिल हुए। तीनों राज्यों के लगभग 2.7 लाख महिला किसानों सहित 27 लाख से अधिक किसानों के बैंक खातों में कुल 540 करोड़ रुपये से अधिक की राशि सीधे अंतरित की गई है।

रबी 2025 के लिए उच्च उत्पादकता वाली गेहूं की नई किस्में

नई दिल्ली (कृषक जगत)। कृषि मंत्रालय के कृषि विभाग ने रबी 2025 सीजन के लिए नई उच्च उपज और जलवायु सहनशील गेहूं की किस्में जारी की हैं। ये किस्में तापमान में उतार-चढ़ाव, सूखा और गर्मी जैसी परिस्थितियों को सहन कर सकती हैं। कुछ किस्मों में अतिरिक्त गुण भी हैं जैसे गेहूं ब्लास्ट रोग से प्रतिरोधक क्षमता, अधिक प्रोटीन की मात्रा, जिनकी प्रचुरता,



चपाती और ब्रेड की बेहतर गुणवत्ता तथा ड्यूरम उत्पादों के लिए उपयुक्तता।

कृषि विभाग का कहना है कि ये किस्में किसानों को बदलती जलवायु परिस्थितियों से बचाव के साथ-साथ बेहतर उपज और गुणवत्ता प्रदान करेंगी। इससे आने वाले वर्षों में देश की खाद्य सुरक्षा मजबूत होगी और किसानों की आमदनी में भी सुधार होगा।

रबी 2025 के लिए जारी जलवायु सहनशील गेहूं की किस्में

किस्म	जोन/उत्पादन परिस्थिति	संभावित उत्पादकता (क्वि./हे.)	औसत उत्पादकता (क्वि./हे.)	विशेषताएं
JKW 261	NWPZ-LS-IR	66.6	51.7	सूखा व गर्मी सहनशील
JKW 296	NWPZ-TS-RI	83.3	56.1	जलवायु सहनशील, बहुउपयोगी
JKW327	NWPZ-IR-ES-HF	87.7	79.4	सूखा व गर्मी सहनशील
JKW 332	NWPZ-IR-ES-HF	83.0	78.3	उच्च प्रोटीन (12.2 प्रतिशत)
HUW 838	NWPZ-TS, RI	77.7	51.3	गेहूं ब्लास्ट रोग प्रतिरोधी
HI 1636	CZ-TS, IR	78.8	56.6	जिनक युक्त (44.4 ppm)
GW 513	CZ-TS, IR	77.4	58.5	चपाती गुणवत्ता (8.36 स्कोर)
MP(JW)1358	CZ-TS, RI	43.6	30.9	सूखा व गर्मी सहनशील
HI 8823 (d)	PZ-TS, RI	65.6	38.5	ड्यूरम उत्पादों के लिए उपयुक्त
DBW 222 (AE)	NEPZ-TS-IR	62.0	48.9	चपाती (7.5) व ब्रेड (8.24) गुणवत्ता
DBW 187 (AE)	CZ-IR-ES-HF	75.4	60.3	उत्तर-पश्चिम, उत्तर-पूर्व व केंद्रीय क्षेत्र के लिए उपयुक्त

संकेताक्षर - NWPZ - उत्तर पश्चिमी मैदान क्षेत्र; NEPZ - उत्तर-पूर्वी मैदान क्षेत्र; CZ - केंद्रीय क्षेत्र; PZ - प्रायद्वीपीय क्षेत्र; TS - समय पर बोई गई फसल; LS - विलंबित बोई गई फसल; ES - जल्दी बोई गई फसल; IR - सिंचित; RI - सीमित सिंचाई; RF - वर्षा आधारित।

आईसीएआर की अ.भा. प्रतियोगी परीक्षा से भरी जाएंगी

कृषि विश्वविद्यालयों की 20 प्रतिशत स्नातक सीटें

केंद्रीय कृषि मंत्री ने कृषि विद्यार्थियों की समस्या का किया समाधान

नई दिल्ली (कृषक जगत)। केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने देश में कृषि शिक्षा से संबंधित एक गंभीर मुद्दे को हल करते हुए कृषि के छात्र-छात्राओं तथा उनके पालकों को बड़ी राहत दी है। अब कृषि विश्वविद्यालयों की 20 प्रतिशत स्नातक सीटें भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) द्वारा आयोजित अखिल भारतीय प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से भरी जाएंगी, जिसमें 'एक देश-एक कृषि-एक टीम' की भावना के अनुरूप, देशभर के छात्रों के लिए पात्रता मानदंड एवं विषय समूह को एक समान कर दिया गया है, जिससे 12वीं में बायोलॉजी, रसायन, भौतिकी, गणित या कृषि विषय समूह लेने वाले विद्यार्थी बराबर पात्रता के साथ राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा (सीयूईटी-आईसीएआर) के जरिये सीधे-पारदर्शी तरीके से दाखिला ले सकेंगे।

केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह ने बताया कि कृषि स्नातक (B.Sc. Agri) में, प्रवेश में कुछ वर्षों से एक बड़ी समस्या छात्र-छात्राओं के लिए अक्षम पात्रता मानदंड की थी, 12वीं में अलग-अलग विषय संयोजनों (कृषि, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स) तथा अलग-अलग राज्यों के अलग-अलग नियमों, अलग-अलग पात्रता के कारण कृषि के ये योग्य छात्र-छात्राएं पिछड़ जाते थे। इस बारे में पिछले कुछ दिनों में सोशल मीडिया के माध्यम से विद्यार्थियों ने समस्या बताई थी, वहीं कुछ राज्यों के जनप्रतिनिधियों ने भी केंद्रीय मंत्री श्री चौहान को इस संबंध में लिखा था, जिस पर उन्होंने संवेदना के साथ तुरंत संज्ञान लिया व विद्यार्थियों की समस्या को गंभीरता से समझकर आईसीएआर के महानिदेशक डॉ. मांगी लाल जाट को निर्देश दिया कि वे राज्यों के कृषि विश्वविद्यालयों एवं उनके कुलपतियों के साथ बातचीत करके इसका त्वरित हल ढूंढने की दिशा में काम करें।

श्री शिवराज सिंह ने कहा कि इससे अब देशभर के छात्र-छात्राओं के लिए प्रवेश के अवसर सुगम तथा एक समान हो गए हैं। इस सुव्यवस्थित व्यवस्था से शैक्षणिक वर्ष 2025-26 से B.Sc. (कृषि) में प्रवेश संबंधित सभी जटिलताएं दूर होकर लगभग तीन हजार विद्यार्थियों को सीधे-सीधे इसका लाभ मिलेगा।

रबी फसलों का समर्थन मूल्य... (प्रथम पृष्ठ का शेष)

3 वर्षों का तुलनात्मक विवरण (रुपए प्रति क्विंटल में)

फसल	2023-24	2024-25	वृद्धि	2025-26
गेहूं	2275	2425	160	2585
जौ	1850	1980	170	2150
चना	5440	5650	225	5875
मसूर	6425	6700	300	7000
सरसों	5650	5950	250	6200
कुसुम	5800	5940	600	6540

सामाजिक सम्मान एवं देश की खाद्य एवं पोषण सुरक्षा को नई मजबूती मिलेगी। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि एमएसपी में सबसे अधिक वृद्धि कुसुम के लिए रु. 600 प्रति क्विंटल की गई है, मसूर के लिए रु. 300 प्रति क्विंटल की गई है। रेपसीड और सरसों, चना, जौ और गेहूं के लिए क्रमशः रु. 250 प्रति क्विंटल, रु.225 प्रति क्विंटल, रु.170 प्रति क्विंटल और रु.160 प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है।

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि देश में दालों के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, पोषण एवं किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से 'राष्ट्रीय दलहन मिशन' मंजूर किया गया है। मिशन का लक्ष्य वर्ष 2030-31 तक दलहन उत्पादन को 242 लाख टन से 350 लाख टन करने का है।

विपणन मौसम 2026-27 के लिए रबी फसलों हेतु एमएसपी में वृद्धि केंद्रीय बजट 2018-19 में एमएसपी को अखिल भारतीय भारित औसत उत्पादन लागत के कम से कम 1.5 गुना के स्तर पर निर्धारित करने की घोषणा के अनुरूप है।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक **विजय कुमार बोन्दिया** द्वारा 14, इंदिरा प्रेस काम्पलेक्स, महाराणा प्रताप नगर, भोपाल से प्रकाशित एवं कृषक जगत 14, इंदिरा प्रेस काम्पलेक्स, भोपाल (मध्य प्रदेश) से मुद्रित, **सम्पादक : सुनील गंगराडे**, फोन : 0755-4248100, 2554864, फैक्स : 0755-2571449. E-mail-info@krishakijagat.org इस अंक का मूल्य रु. 12/- वार्षिक शुल्क रु. 600/- भारत के समाचार पत्रों के पंजीयक कार्यालय का पंजीयन क्रमांक 1832/57

कृषक जगत

संस्थापक : स्व. माणिकचन्द्र बोन्दिथा - स्व. सुरेशचन्द्र गंगराडे

अमृत जगत

 जो मनुष्य अपने वचन पर दृढ़ रहता है,
 उसके बारे में मुझे कोई संदेह नहीं रहता। - महात्मा गांधी

मध्यप्रदेश में सोयाबीन की फसल खरीदी के लिए भावांतर भुगतान योजना के तहत 3 अक्टूबर से पंजीयन शुरू हो चुका है तथा सोयाबीन उत्पादक किसान आगामी 17 अक्टूबर तक पंजीयन करा सकेंगे। सरकार ने घोषणा की है कि इसी महीने 24 अक्टूबर से सोयाबीन की खरीदी शुरू होगी जो 15 जनवरी तक चलेगी। सरकार ने इस साल सोयाबीन का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 5328 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है। अगर किसानों को मंडियों में इससे कम मूल्य मिलता है तो अंतर वाली राशि सीधे किसान के खाते में भेजी जाएगी। पढ़ने और सुनने में भावांतर योजना किसानों के हित में प्रतीत होती है। यदि ऐसा होता तो किसानों के प्रतिनिधि संगठन भावांतर योजना को पूरी तरह असफल बताते हुए इसे तत्काल बंद करने की मांग कर रहे हैं वहीं सरकार योजना को किसानों के हित में बता रही है। भारतीय किसान संघ का कहना है कि पहले भी भावांतर योजना को लागू किया जा चुका है और पूरी तरह असफल रही है।

संघ का आरोप है कि पिछले वर्षों में लागू की गई भावांतर योजना का करीब ढाई सौ करोड़ रुपये किसानों को भुगतान किया जाना बाकी है। मध्यप्रदेश की अधिकांश मंडियों में नए सोयाबीन की आवक शुरू हो चुकी है और लगभग सभी मंडियों में 5 हजार रुपये

भावांतर योजना : किसानों या व्यापारियों के हित में !

से कम भाव पर ही बिक रहा है। जब सरकार ने ही सोयाबीन का न्यूनतम समर्थन मूल्य 5328 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया है तब किसानों को एमएसपी से कम कीमत मिलने से किसानों का गुस्सा जायज है। किसान सोयाबीन की कीमत 6 हजार रुपये प्रति क्विंटल करने की मांग कर रहे हैं। सरकार का कहना है कि जिन किसानों की सोयाबीन की उपज साफ-सुथरी और गुणवत्ता की होगी, उसी को एमएसपी की दर से कम कीमत मिलने पर भावांतर योजना का लाभ मिलेगा यानी यदि सोयाबीन न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम कीमत पर बिकता है तो किसान को वास्तविक विक्रय मूल्य और न्यूनतम समर्थन मूल्य के बीच का अंतर की राशि का भुगतान किया जाएगा।

आमतौर पर बाजार और मंडियों में अधिक आवक होने पर कीमतें कम हो जाती हैं जिसका नुकसान किसानों को उठाना पड़ता है। लेकिन भावांतर योजना के कार्यावयन का कटु अनुभव रहा है कि कम ही अवसरों पर कीमतें न्यूनतम समर्थन मूल्य के स्तर को छू पाती है। इससे यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि व्यापारी जान-बूझकर कीमतें इसलिए बढ़ने नहीं देते क्योंकि वास्तविक कीमत और न्यूनतम समर्थन मूल्य के बीच के अंतर की भरपाई सरकार तो कर ही देगी जिससे किसानों को कम से कम न्यूनतम समर्थन मूल्य के तहत फसल की कीमत तो मिल ही जाएगी। इसी मानसिकता के कारण जिन फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू है, उनकी कीमतों में अन्य फसलों की अपेक्षा कम ही वृद्धि होती है और इसका नुकसान सरकार को भी होता है। सरकार को चाहिये कि सोयाबीन सहित अन्य सभी फसलों जो न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत

शामिल की गई हैं, उनकी गुणवत्ता के आधार पर खरीदी करना सुनिश्चित करें। फसल की गुणवत्ता के मापदण्ड के लिए जिला स्तर पर एक समिति बनानी चाहिए ताकि वह बिना किसी दबाव के अपना काम कर सके। समिति में किसानों के प्रतिनिधि भी होने चाहिए। भावांतर योजना भले ही किसानों के हित के लिए संचालित की जा रही है लेकिन इससे किसानों से ज्यादा व्यापारी वर्ग लाभान्वित होगा।

किसानों को तो योजना के तहत न्यूनतम समर्थन मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर प्राप्त हो जाएगा लेकिन सरकार को व्यर्थ ही करोड़ों रुपये का आर्थिक बोझ उठाना पड़ेगा। इसलिए सरकार को कोशिश करनी चाहिए कि न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिसूचित उपज कम मूल्य पर न बिके। यदि इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो निश्चित ही अच्छी गुणवत्ता की उपज होने के बावजूद कीमतें न्यूनतम समर्थन मूल्य के बराबर या इससे अधिक कीमत मिल जाएगी। यह तभी हो सकता है जब फसल का उत्पादन बहुत कम हुआ है। भावांतर योजना के तहत पंजीयन और खरीदी का कार्य शुरू हो चुका है इसलिये यह ध्यान रखना होगा कि किसानों को अधिसूचित फसल का कम से कम न्यूनतम समर्थन मूल्य अवश्य मिले। कोशिश यह भी करनी होगी कि यदि व्यापारी कम कीमत पर खरीदने की कोशिश करते हैं तो सरकार स्वयं खरीदे और देश में ही खपत के साथ निर्यात के भी प्रयास करे। इससे किसानों को उनकी फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य तो मिलेगा ही, सरकार को भी आर्थिक हानि नहीं उठानी पड़ेगी। इसलिए सरकार को चाहिए कि मंडियों में आवक और उसकी कीमत पर नजर रखें ताकि जरूरत पड़ने पर हस्तक्षेप कर व्यापारियों को अनावश्यक रूप से लाभ उठाने से रोका जा सके।

नई सदी की सबसे बड़ी चुनौती

● कुमार सिद्धार्थ

आपने कभी सोचा है कि अकेलापन सिर्फ एक भावनात्मक अनुभव नहीं, बल्कि हमारे स्वास्थ्य के लिए उतना ही हानिकारक हो सकता है जितना धूम्रपान या मोटापा? बुजुर्गों में यह हृदय रोग का कारण बन सकता है, और मजबूत सामाजिक संबंध मस्तिष्क के स्वास्थ्य को बेहतर बनाते हैं। एक शोध समीक्षा बताती है कि 18 से 29 वर्ष की उम्र में अकेलापन अपने चरम पर होता है। हर तीन में से एक युवा इस अनुभव से गुजरता है, जिससे मानसिक स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। वास्तव में, 2024 के एक अध्ययन में पाया गया कि अकेलेपन से आत्महत्या के जोखिम को 16 गुना तक बढ़ा सकता है।

यही नहीं, हार्वर्ड की एक रिपोर्ट बताती है कि 18-25 वर्ष के हर तीन में से एक युवा अकेला महसूस करता है, और उनमें से आधे से ज्यादा ने यह माना कि उनके जीवन में उद्देश्य या अर्थ की कमी है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार, हर साल वैश्विक स्तर पर 8 लाख लोग आत्महत्या करते हैं, जबकि आत्महत्या का प्रयास करने वालों की संख्या इससे लगभग 20 गुना अधिक होती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन भी मानता है कि अकेलेपन और सामाजिक अलगाव की भावना आत्महत्या के प्रमुख जोखिम कारकों में से एक हो सकती है।

अब ज़रा वृद्धावस्था की ओर देखिए। शोध बताते हैं कि अकेलेपन से डिमेंशिया का खतरा 31 प्रतिशत तक बढ़ जाता है। 'नेचर मेंटल हेल्थ' में प्रकाशित एक रिपोर्ट कहती है कि जो लोग अकेलेपन से जुड़ते हैं, उनमें भूलने की बीमारी (डिमेंशिया) होने की संभावना अधिक होती है। फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर मार्टिना लुचेती बताती हैं कि सामाजिक संपर्क की कमी और कम दोस्त होने से मेमोरी लॉस यानी याददाश्त खोने की समस्या बढ़ सकती है।

अब सवाल उठता है कि क्या यह सिर्फ मानसिक

स्वास्थ्य तक सीमित है? नहीं। 2018 के एक अध्ययन ने दिखाया कि अकेलापन स्ट्रोक का खतरा 32 फीसदी और कोरोनरी हार्ट डिजीज का खतरा 29 फीसदी तक बढ़ा सकता है। जब लोग अकेला महसूस करते हैं, तो तनाव बढ़ जाता है, जिससे हार्ड बीपी और



सूजन जैसी समस्याएँ जन्म लेती हैं।

शोध बताते हैं कि यदि अकेलेपन को कम किया जाए, तो अवसाद के मामलों में उल्लेखनीय कमी लाई जा सकती है। इसके लिए हमें सामुदायिक और व्यक्तिगत स्तर पर सक्रिय प्रयास करने होंगे। जब कोई व्यक्ति सामुदायिक कार्यक्रमों में भाग लेता है या सामाजिक समूहों से जुड़ता है, तो वह खुद को अधिक जुड़ा हुआ महसूस करता है। मनोवैज्ञानिक परामर्श और थेरेपी भी उन लोगों के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है, जो लंबे समय से अकेलेपन का सामना कर रहे हैं। इसके अलावा, डिजिटल प्लेटफॉर्मों का सही उपयोग करके परिवार और दोस्तों से जुड़े रहना, भावनात्मक मजबूती प्रदान कर सकता है। ऐसे में, सामाजिक अलगाव और अकेलापन स्वास्थ्य और सामाजिक नीति अनुसंधान के महत्वपूर्ण विषय बन गए हैं। दुनिया के कुछ देशों ने नई सदी के इस संकट को पहचाना है। अमेरिकी सरकार ने अकेलापन, सामाजिक अलगाव और सामाजिक संपर्क बढ़ाने के

समाधान के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया है। अमेरिकी सरकार की तरफ से पिछले साल मई में जारी एक रिपोर्ट कहती है कि महामारी से पहले भी देश के वयस्कों की लगभग आधी आबादी औसत स्तर के अकेलेपन से जूझ रही थी। डेनमार्क सरकार ने भी अकेलेपन को कम करने के लिए एक राष्ट्रीय पहल शुरू की है। इसमें सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देने और सामाजिक एकांत के प्रभावों को कम करने

अकेलापन अब सिर्फ भावनात्मक अनुभव नहीं रहा, बल्कि यह धूम्रपान और मोटापे जितना घातक स्वास्थ्य संकट बन चुका है। यह युवाओं में आत्महत्या के जोखिम को कई गुना बढ़ाता है और बुजुर्गों में हृदय रोग व डिमेंशिया का बड़ा कारण बनता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे गंभीर वैश्विक स्वास्थ्य समस्या मानते हुए सामाजिक जुड़ाव को प्राथमिकता देने पर जोर दिया है।

पर जोर दिया गया है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अकेलेपन को एक गंभीर जन स्वास्थ्य समस्या के रूप में स्वीकार किया है, जो दुनिया की एक चौथाई आबादी को प्रभावित कर रही है। यह केवल एक सामाजिक मुद्दा नहीं, बल्कि एक ऐसी स्वास्थ्य चुनौती है, जो दीर्घकाल में कई शारीरिक और मानसिक बीमारियों को जन्म दे सकती है। इससे निपटने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सामाजिक जुड़ाव को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक वैश्विक आयोग की घोषणा की। इस आयोग में कुल 11 सदस्य शामिल हैं, जिन्हें तीन महत्वपूर्ण जिम्मेदारियाँ सौंपी गई हैं वैश्विक स्तर पर सामाजिक जुड़ाव को प्राथमिकता देने के लिए एक स्पष्ट एजेंडा तैयार करना, अकेलेपन और सामाजिक अलगाव के दुष्प्रभावों को लेकर जागरूकता फैलाना, साक्ष्य-आधारित समाधानों के लिए विभिन्न देशों, संगठनों और नीति-निर्माताओं के साथ सहयोग करना।

विश्व स्वास्थ्य संगठन का यह कदम अकेलेपन

को एक गंभीर स्वास्थ्य संकट के रूप में पहचानने और इसे कम करने के लिए ठोस प्रयासों को सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। यह आयोग दुनिया भर में सामाजिक संबंधों को मजबूत करने और मानसिक स्वास्थ्य पर इसके सकारात्मक प्रभावों को बढ़ावा देने का काम करेगा।

भारत में अकेलेपन और अवसाद से निपटने के लिए वर्तमान में कोई विशिष्ट राष्ट्रीय नीति नहीं बनी है, जबकि कई अन्य देशों ने इस दिशा में पहल की है। 2015-2016 में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी 'नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे' में भी अकेलेपन का जिक्र नहीं किया गया। हालांकि, मानसिक स्वास्थ्य को संबोधित करने के लिए सरकार ने कई पहलों की हैं। 2017 में, 'मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम' लागू किया गया, जो मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच को सुनिश्चित करता है और मानसिक रोगियों के अधिकारों की रक्षा करता है। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के माध्यम से मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार और सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है। वहीं वर्तमान में, भारत में बुजुर्गों से संबंधित दो राष्ट्रीय नीतियाँ मौजूद हैं, लेकिन उनमें भी अकेलेपन पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया है। 1999 में जारी 'राष्ट्रीय बुजुर्ग नीति' में अकेलेपन का जिक्र सिर्फ एक बार हुआ है।

अकेलेपन और सामाजिक अलगाव की बढ़ती समस्या को देखते हुए, भारत में भी एक समग्र नीति की आवश्यकता महसूस की जा रही है, जो मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक सहभागिता और सामुदायिक समर्थन को बढ़ावा देने पर केंद्रित हो। इन नीतियों में सामुदायिक जुड़ाव को प्रोत्साहित करना, मानसिक स्वास्थ्य शिक्षा को बढ़ावा देना, और सामाजिक समर्थन नेटवर्क को मजबूत करना शामिल हो सकता है। इससे न केवल मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुँच बढ़ेगी, बल्कि समाज में मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता और संवेदनशीलता भी बढ़ेगी। सवाल सिर्फ यह है कि हम इसके लिए कितने तैयार हैं? (सप्रेम)



फव्वारा सिंचाई : लाभकारी सूक्ष्म सिंचाई पद्धति

- डॉ. राजेश गुप्ता ● डॉ. जी.एस. चुण्डावत
 - डॉ. निशित गुप्ता
 - डॉ. एस.पी. त्रिपाठी ● श्री संतोष पटेल
- rajgupta171@gmail.com

भूजल के अंधाधुंध दोहन के कारण इसके स्तर में तेजी से गिरावट आ रही है। सिंचाई की परंपरागत प्रवाह विधि में अधिक जल खपत के कारण भी जल की उपयोग दक्षता पर ध्यान दिया जाना जरूरी है। इसके अतिरिक्त सिंचाई क्षेत्र में सरकारी एवं निजी स्तरों पर अथक प्रयास के बावजूद अभी भी देश के शुद्ध कृषि क्षेत्रफल के आधे से कम (लगभग 49 प्रतिशत) हिस्से में सिंचाई सुविधा सृजित की जा सकी है। शेष बुआई क्षेत्रफल मानसूनी वर्षा पर निर्भर रहता है। जलवायु परिवर्तन का असिंचित (बारानी) क्षेत्रों पर सर्वाधिक असर होता है। एक अनुमान के अनुसार बारानी फसलों से प्राप्त वार्षिक आमदनी सिंचित क्षेत्रों की अपेक्षा 25-30 प्रतिशत कम होती है। ऐसी स्थिति में सिंचाई की उन्नत विधियों (फव्वारा एवं टपक) के तहत अधिक कृषि क्षेत्रफल को लाने की आवश्यकता है। इससे

कृषि एवं पशुपालन में जल एक महत्वपूर्ण उत्पादन कारक है। इन कारकों की मात्रात्मक वृद्धि एवं इनकी प्रयोग दक्षता बढ़ाने में भी जल काफी सहायक होता है। देश में कुल उपलब्ध जल का लगभग 78 प्रतिशत हिस्सा कृषि में सिंचाई के रूप में प्रयुक्त होता है। जलवायु परिवर्तन, मानसूनी वर्षा में आ रही लगातार गिरावट एवं अनियमितता की वजह से जल की घटती उपलब्धता तथा अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों की बढ़ती मांग भविष्य में जल की भारी कमी की तरफ संकेत करते हैं। एक अनुमान के अनुसार वर्ष 2050 तक कृषि में जल की कमी उपलब्धता घटकर 68 प्रतिशत तक आने की आशंका है। नीति आयोग की रिपोर्ट में देश में जल की भयावह स्थिति के बारे में बताया गया है एवं अन्य वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर भी कृषि में जल की भयावह स्थिति के बारे में बताया गया है। अन्य वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर कृषि में जल की खपत को 50 प्रतिशत से नीचे लाने की आवश्यकता पर बल दिया जा रहा है। खेती में सिंचाई के लिए भूजल का लगभग एक तिहाई हिस्सा उपयोग किया जाता है।

उपलब्ध जल का समुचित एवं लाभकारी प्रयोग हो सकेगा तथा प्रति बूंद अधिक उपज एवं आमदनी प्राप्त की जा सकेगी। अतएव कृषि में जल की उपलब्धता बनाये रखने, अधिक क्षेत्रफल में सिंचाई करने तथा लागत में कमी लाने के लिए फव्वारा सिंचाई विधि खाद्यान्न फसलों के लिए एक उचित विकल्प है। इस सिंचाई पद्धति में जल को छिड़काव के रूप में फसलों को दिया जाता है। इससे जल पौधों पर बारिश की बूंदों की तरह पड़ता है एवं खेत में जल भराव भी नहीं होता

है। इस विधि से सिंचाई भूमि के ढलान के अनुरूप की जा सकती है एवं मृदा संरक्षण में सहायता मिलती है। सिंचाई की इस पद्धति में पौधों को समान मात्रा में जल मिलता है, जिससे उनकी समान वृद्धि से अधिक उत्पादकता सुनिश्चित होती है। अनाज फसलों के अतिरिक्त दलहनी एवं तिलहनी फसलों के लिए भी यह विधि बहुत उपयोगी है। इन फसलों में कम जल की आवश्यकता होती है।

सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली, जल उपयोग दक्षता बढ़ाने के साथ-साथ अधिक क्षेत्रफल में सिंचाई सुविधा सुनिश्चित करती है। इस पद्धति में दो सिंचाई विधियाँ-फव्वारा तथा टपक (बूंद-बूंद) प्रचलित हैं। जल की घटती उपलब्धता एवं अन्य क्षेत्रों में जल की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए सूक्ष्म सिंचाई को मांग-प्रबंधन रणनीति के तौर पर वर्ष 2005-06 में एक केन्द्र प्रायोजित योजना के रूप में शुरू किया गया था। इस योजना की समीक्षा बैठकों में समय के साथ इसमें बदलाव किये गये। वर्ष 2010 में उपरोक्त स्कीम को 'सूक्ष्म सिंचाई पर राष्ट्रीय मिशन' और वर्ष 2014 में फिर इसे 'सतत कृषि में राष्ट्रीय मिशन' के अंतर्गत प्रक्षेत्र स्तर पर जल प्रबंधन के रूप में शुरू किया गया। वर्तमान में सूक्ष्म सिंचाई एवं सिंचाई की अन्य योजनाओं को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (2015) के तहत समाहित कर दिया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य 'हर खेत को जल' तथा 'प्रति बूंद अधिक उपज' प्राप्त करना है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई कार्यक्रम के लागू होने के बाद के वर्षों में सूक्ष्म सिंचाई क्षेत्रफल बढ़कर 9.2

मिलियन हेक्टर हो गया है। यह इस विधि के तहत लाये जाने वाले संभावित क्षेत्रफल (69.5 मिलियन हेक्टर) का लगभग 13 प्रतिशत है।

फव्वारा सिंचाई पद्धति की सीमायें

फव्वारा सिंचाई पद्धति की प्रारंभिक लागत अधिक होती है। बिजली की अधिक आवश्यकता और उपकरण की कीमत अधिक होती है। वर्गाकार अथवा आयताकार खेत के लगभग 10-2% भाग की सिंचाई नहीं हो पाती है। वर्गाकार और आयताकार खेत की सिंचाई के लिए सेंटर-पाइवट सिस्टम में आने वाली समस्याओं को दूर करते हुए अब लैटरल-मूव सिस्टम विकसित किया गया है। यह सिंचाई पद्धति लैटरल-मूव सिस्टम का बना होता है जो खेत में ऊपर-नीचे घूमता रहता है।

फव्वारा सिंचाई पद्धति में रखरखाव एवं सावधानियाँ

फव्वारा सिंचाई के प्रयोग के समय एवं प्रयोग के बाद परीक्षण कर लें और कुछ मुख्य सावधानियाँ रखने से सेट अच्छी तरह चलता है। जैसे - प्रयोग होने वाला सिंचाई जल स्वच्छ तथा बालू एवं अत्यधिक मात्रा घुलनशील तत्वों से युक्त हो तथा उर्वरकों, फफूंदी, खरपतवारनाशी आदि दवाओं के प्रयोग के पश्चात सम्पूर्ण प्रणाली को स्वच्छ पानी से सफाई कर लें। प्लास्टिक वाशरों को आवश्यकता अनुसार निरीक्षण करते रहें और बदलते रहें। रबर सील को साफ रखें तथा प्रयोग के बाद अन्य फिटिंग भागों को अलग कर साफ करने के उपरान्त शुष्क स्थान पर भण्डारित करें।

सूक्ष्म सिंचाई पद्धति के अंतर्गत फव्वारा सिंचाई जल की मांग-आपूर्ति के बीच अंतर कम करने एवं इसकी उपयोग दक्षता बढ़ाने का एक उचित विकल्प है। पिछले कुछ वर्षों में सूक्ष्म सिंचाई के अंतर्गत आच्छादित क्षेत्रफल में काफी बढ़ोतरी हुई है। इसलिए सिंचाई की फव्वारा विधि को व्यापक स्तर पर अपनाने इसमें सुधार और किसानों के बीच इसके प्रचार-प्रसार के लिए और अधिक समन्वित प्रयास किए जाने की आवश्यकता है।

फव्वारा सिंचाई पद्धति के लाभ

- सतही सिंचाई में पानी खेत तक पहुँचने में 15-20 प्रतिशत दूर तक अनुपयोगी रहता है। नहर के पानी से यह हानि 30-50 प्रतिशत तक बढ़ जाती है और सतही सिंचाई में एक सा पानी नहीं पहुँचता जबकि फव्वारा सिंचाई से सिंचित क्षेत्रफल 1.5 से 2 गुना बढ़ जाता है अर्थात् इस विधि से सिंचाई करने पर 25-50 प्रतिशत तक पानी की सीधे बचत होती है।
- जब पानी वर्षा की भांति छिड़का जाता है तो भूमि पर जल भराव नहीं होता है जिससे मिट्टी की पानी सोखने की दर में वृद्धि होती है और कम पानी के बहने से हानि नहीं होती है।
- जिन जगहों पर भूमि ऊँची-नीची रहती है वहाँ पर सतही सिंचाई संभव नहीं हो पाती और उन जगहों पर फव्वारा सिंचाई वरदान साबित होती है।
- फव्वारा सिंचाई अधिक ढाल वाली तथा ऊँची-

- नीची जगहों के लिए सर्वोत्तम विधि है। इन जगहों पर सतही विधि से सिंचाई नहीं की जा सकती है।
- इस विधि से सिंचाई करने पर मृदा में नमी का उपयुक्त स्तर बना रहता है जिसके कारण फसल की वृद्धि उपज और गुणवत्ता अच्छी रहती है।
- इस विधि में सिंचाई के पानी के साथ घुलनशील उर्वरक, कीटनाशी तथा जीवनाशी या खरपतवारनाशी दवाओं का भी प्रयोग आसानी से किया जा सकता है।
- पानी की कमी, सीमित पानी की उपलब्धता वाले क्षेत्रों में सतही सिंचाई की अपेक्षा फव्वारा सिंचाई पद्धति से दुगुना से तीन गुना क्षेत्रफल सिंचित किया जा सकता है।
- पाला पड़ने से पहले फव्वारा सिंचाई पद्धति से सिंचाई करने पर तापक्रम बढ़ जाने से फसल का पाले से नुकसान नहीं होता है।



- डॉ. दीपक हरि रानडे • डॉ. मनोज कुरील
- डॉ. स्मिता अग्रवाल

कृषि महाविद्यालय, खंडवा

खंडवा कृषि महाविद्यालय परिसर का 'पारिजात' वृक्ष सिर्फ एक पौधा नहीं, बल्कि सुगंध, औषधि और संस्कृति का अनोखा

उपहार है।

इस वृक्ष के सफेद फूलों की नारंगी झलक जब रात में खिलकर सुबह ज़मीन पर बिछ जाती है, तो पूरा वातावरण सौंदर्य और सुगंध से भर जाता है। यही कारण है कि इसे लोग न केवल प्रकृति का चमत्कार मानते हैं, बल्कि पूजा और श्रद्धा से भी जोड़ते हैं।

पारिजात

सुगंध, औषधि और आस्था का अद्भुत संगम

औषधीय और कृषि महत्व

पारिजात की पत्तियाँ और फूल कई रोगों की औषधि हैं। आयुर्वेद में इसका उपयोग बुखार, जोड़ों के दर्द, मलेरिया और त्वचा रोगों के उपचार में किया जाता है। इसके फूलों से प्राकृतिक रंग भी बनाया जाता है, जो कपड़ों और खाद्य उत्पादों में काम आता है। सिर्फ औषधि ही नहीं, यह वृक्ष किसानों और पर्यावरण

के लिए भी वरदान है। इसकी खुशबू और फूल मधुमक्खियों व तितलियों को आकर्षित करते हैं, जिससे आसपास की फसलों में परागण बढ़ता है और जैव विविधता भी सुरक्षित रहती है।

धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व

शास्त्रों में पारिजात का विशेष उल्लेख है। कहा जाता है कि यह वृक्ष समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ और भगवान कृष्ण ने इसे द्वारका में लगाया था। आज भी इसके फूल विष्णु, शिव और दुर्गा की पूजा में चढ़ाए जाते हैं। खासकर नवरात्र और शरद पूर्णिमा पर इसकी मांग बहुत रहती है।

रात को ही क्यों खिलते हैं फूल?

पारिजात के फूलों का रहस्य भी कम रोचक नहीं है। ये फूल रात को खिलते हैं क्योंकि इनके मुख्य परागणकर्ता रात में सक्रिय कीट-पतंगे होते हैं। ठंडी और नमी वाली रात में इसकी सुगंध दूर तक फैलती है। सुबह होते ही फूल ज़मीन पर गिर जाते हैं, ताकि पौधा अपनी ऊर्जा और नमी बचा सके। यही झरे हुए फूल लोगों की पूजा और रंग बनाने में काम आते हैं।

जैव विविधता और प्रेरणा

खंडवा कृषि महाविद्यालय का यह पारिजात वृक्ष न सिर्फ छात्रों के लिए अध्ययन और शोध का विषय है, बल्कि यह उन्हें प्रकृति से जुड़ाव और संरक्षण की प्रेरणा भी देता है। इसकी छाँव में बैठने वाला हर व्यक्ति एक अद्भुत शांति और ताजगी का अनुभव करता है।

सचमुच, पारिजात सिर्फ एक वृक्ष नहीं, बल्कि प्रकृति, आस्था और विज्ञान का सुंदर संगम है।

घोड़ा नीम (बकाइन)

जैव विविधता और बहुउपयोगिता का साथी

नीम और घोड़ा नीम दोनों के औषधीय व कीटनाशक गुण होते हैं, लेकिन इनमें कुछ फर्क है। घोड़ा नीम की पत्तियाँ बड़ी और हल्की हरी होती हैं तथा स्वाद में नीम की तरह बहुत कड़वी नहीं होती। इसके फूल बैंगनी-गुलाबी रंग के होते हैं और फल छोटे बेर जैसे गोल होते हैं। वहीं साधारण नीम के फूल सफेद और फल अंडाकार होते हैं। औषधीय दृष्टि से साधारण नीम अधिक प्रभावी है, पर घोड़ा नीम भी हल्के कीटनाशक और औषधीय उपयोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण है।

ग्रामीण जीवन से जुड़ा साथी

गाँवों में आज भी लोग इसके पत्तों का उपयोग अनाज भंडारण में करते हैं, ताकि कीड़े न लगें। खेतों में इसे छायादार वृक्ष के रूप में लगाया जाता है। इसके फल और पत्तियाँ थोड़ी मात्रा में पशुओं के चारे के काम भी आती हैं। लकड़ी हल्की लेकिन टिकाऊ होती है, जिससे ग्रामीण इलाकों में फर्नीचर, खिलौने और कृषि उपकरण बनाए जाते हैं।

गाँव की दादी-नानी अक्सर इसके छाल का काढ़ा बुखार और पेट की तकलीफ में देती थीं। पत्तियों का लेप चर्म रोगों और फोड़े-फुसियों पर लगाया जाता है। वहीं इसके फूल और फल मधुमक्खियों, पक्षियों और अन्य जीवों के लिए भोजन का स्रोत हैं, जिससे परागण और पर्यावरणीय संतुलन बना रहता है।

कृषि महाविद्यालय खंडवा के हरे-भरे परिसर में वर्षों से खड़ा घोड़ा नीम का विशाल वृक्ष न केवल छात्रों और शिक्षकों को छाया देता है, बल्कि जैव विविधता और उपयोगिता का एक जीवंत उदाहरण भी है। आमतौर पर इसे 'बकाइन' कहा जाता है। यह वृक्ष दिखने में आकर्षक होने के साथ-साथ पर्यावरण, कृषि और औषधि - तीनों क्षेत्रों में उपयोगी साबित होता है।

सावधानी भी जरूरी

जहाँ इसके कई फायदे हैं, वहीं कुछ नुकसान भी हैं। इसके फल और बीज अधिक मात्रा में खाने पर विषैले हो सकते हैं, इसलिए इन्हें पशुओं को



बहुत सोच-समझकर दिया जाता है। इसकी जड़ें आसपास के पौधों के पोषक तत्व खींच लेती हैं, जिससे पास की फसलें प्रभावित हो सकती हैं।

भविष्य की संभावनाएँ

वैज्ञानिक दृष्टि से भी घोड़ा नीम में कई संभावनाएँ छिपी हैं। इसके पत्तों और फलों से जैविक कीटनाशक बनाए जा सकते हैं। इसके औषधीय गुणों का गहन परीक्षण किया जा सकता है। जैव विविधता संरक्षण, परागण प्रणाली और मिट्टी की सेहत पर इसके प्रभाव का अध्ययन भी कृषि अनुसंधान को नई दिशा दे सकता है। कुल मिलाकर, घोड़ा नीम सिर्फ एक पेड़ नहीं, बल्कि ग्रामीण जीवन का साथी, प्रकृति का संरक्षक और आने वाले समय की वैज्ञानिक खोजों का आधार है।

पशु स्वास्थ्य की ढाल - समय पर टीकाकरण

• डॉ. महेन्द्र सिंह मील • डॉ. श्रुति गर्ग
पशुचिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय,
नवानिया, वल्लभनगर, उदयपुर (राज.)

टीकाकरण की आवश्यकता

रोगों से बचाव: टीकाकरण के बाद पशु की शरीर प्रतिरोधक क्षमता (इम्यूनिटी) बढ़ती है और वह रोगों से लड़ने में सक्षम होता है।

उत्पादन क्षमता में वृद्धि: स्वस्थ पशु अधिक दूध, मांस और अंडे देते हैं।

आर्थिक बचत: रोग लगने के बाद इलाज में ज्यादा खर्च आता है, जबकि टीका सस्ता और सुरक्षित उपाय है।

रोगों का प्रसार रोकना: संक्रामक रोग जैसे खुरपका-मुंहपका और गलघोटू तेजी से फैलते हैं। टीकाकरण से पूरे झुंड और गाँव सुरक्षित रहते हैं।

मानव स्वास्थ्य की सुरक्षा: कुछ रोग जैसे ब्रूसेल्लोसिस और रेबीज पशुओं से इंसानों में भी

फैलते हैं। टीकाकरण से जूनोटिक रोगों पर नियंत्रण पाया जा सकता है।

सामान्य पशु रोग जिनमें टीकाकरण आवश्यक है

खुरपका-मुंहपका: यह गाय, भैंस, बकरी और भेड़ में पाया जाने वाला सबसे खतरनाक संक्रामक रोग है। इसमें पशु के मुँह, जीभ और खुरों में छाले पड़ जाते हैं जिससे वह खाना-पीना छोड़ देता है और दूध उत्पादन अचानक कम हो जाता है।

भारत जैसे कृषि प्रधान देश में पशुधन किसानों की रीढ़ है। दूध, मांस, अंडे, ऊन और गोबर जैसे उत्पाद न केवल किसानों की आय बढ़ाते हैं, बल्कि पोषण और पर्यावरण संरक्षण में भी योगदान करते हैं। लेकिन जब पशु बीमार पड़ते हैं तो उनकी उत्पादन क्षमता घट जाती है, कभी-कभी जान का नुकसान भी हो जाता है। इन रोगों से बचाव का सबसे सरल और प्रभावी उपाय है समय पर टीकाकरण। टीकाकरण को पशु स्वास्थ्य की 'ढाल' कहा जा सकता है, क्योंकि यह पशुओं को गंभीर और संक्रामक रोगों से सुरक्षित रखता है।

गलघोटू: यह रोग वर्षा ऋतु में अधिक होता है। इसमें पशु को तेज बुखार, सांस लेने में कठिनाई



किसानों को होने वाले लाभ

- **उच्च दूध उत्पादन:** रोगों से मुक्त पशु अधिक दूध देते हैं।
- **बच्चों की मृत्यु दर कम:** नवजात बछड़े और मेमने सुरक्षित रहते हैं।
- **बीमारी का खतरा घटे:** पशुओं का इलाज, दवा और मजदूरी पर होने वाला खर्च बचे।
- **झुंड की सुरक्षा:** एक पशु बीमार हुआ तो पूरा झुंड खतरे में आता है। टीकाकरण से यह खतरा टलता है।
- **किसान की आय में वृद्धि:** स्वस्थ पशु किसान की आर्थिक स्थिति को मजबूत करते हैं।

किसानों के लिए सुझाव

- सभी पशुओं का समय पर टीकाकरण कराएँ।
- टीकाकरण के समय पशु पूरी तरह स्वस्थ होना चाहिए।
- गर्भित पशुओं और छोटे बच्चों में कुछ टीके नहीं लगते, इसलिए डॉक्टर की सलाह लें।
- टीकाकरण के बाद हल्का बुखार या सूजन आना सामान्य है। घबराएँ नहीं।
- टीकाकरण के साथ-साथ कीड़ा मुक्ति भी समय पर कराएँ।

पशु टीकाकरण कैलेंडर

रोग	टीकाकरण की आयु/समय	टीकाकरण की आवृत्ति	विशेष टिप्पणी
खुरपका-मुंहपका	सभी उम्र के पशु- मार्च/अप्रैल एवं सितंबर/अक्टूबर	वर्ष में 2 बार	पूरे झुंड को एक साथ टीका लगाएँ।
गलघोटू	सभी उम्र के पशु - बरसात से पहले (मई/जून)	वर्ष में 1 बार	खासकर गाय-भैंस में अनिवार्य।
काला ज्वर	6 माह से 2 वर्ष तक के बछड़े बरसात से पहले (मई/जून)	वर्ष में 1 बार	बछड़ों में अधिक आवश्यक।
ब्रूसेल्लोसिस	4-8 माह की मादा बछड़ी	जीवन में केवल 1 बार	गर्भवती और दूध देने वाली गाय/भैंस को न लगाएँ।
रेबीज	जोखिम वाले क्षेत्रों में (कुत्ते/सियार प्रकोप)	वर्ष में 1 बार	मनुष्यों के लिए भी सुरक्षा देता है।

किसानों को चाहिए कि नजदीकी पशु चिकित्सालय से परामर्श लेकर अपने पशुओं का टीकाकरण कैलेंडर बनवाएँ।

और गले में सूजन हो जाती है, जिससे अचानक मौत हो सकती है।

काला ज्वर: यह रोग विशेषकर 6 माह से 2 वर्ष तक की उम्र के बछड़ों में होता है। मांसपेशियों में सूजन और दर्द के कारण पशु लंगड़ाने लगता है और अक्सर मृत्यु हो जाती है।

ब्रूसेल्लोसिस: यह रोग मुख्यतः गर्भपात और बांझपन का कारण बनता है। यह मनुष्यों में भी फैल सकता है, इसलिए इसका टीकाकरण बहुत जरूरी है।

रेबीज (हाइड्रोफोबिया): पागल कुत्ते के काटने से होने वाला यह रोग घातक है। पशुओं और मनुष्यों दोनों को प्रभावित करता है। टीकाकरण से इसकी रोकथाम संभव है।

टीकाकरण पशु स्वास्थ्य और किसान की समृद्धि दोनों के लिए वरदान है। समय पर टीका लगाकर हम न केवल अपने पशुओं को रोगमुक्त रखते हैं, बल्कि पूरे गाँव और समाज को सुरक्षित करते हैं। याद रखें - 'टीकाकरण ही है पशु स्वास्थ्य की सच्ची ढाल।'

कामयाब किसान की कहानी

पशुपालन व्यवसाय में प्रगति की राह पर राहुल



उपलब्ध कराई जाती हैं, जिनकी दूध देने की क्षमता प्रतिदिन लगभग 10 लीटर होती है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना, रोजगार के अवसर सृजित करना एवं दूध उत्पादन को बढ़ावा देना है। सरकारी योजनाएं लाभार्थी को जीवन में आगे बढ़ने में मदद करती हैं।

जिले के ग्राम इच्छापुर के पशुपालक श्री राहुल चौहान लाभान्वित हुए हैं। पशुपालक राहुल, सरकारी योजनाओं की मदद से अपने पशुपालन व्यवसाय को बढ़ाकर तरक्की की ओर बढ़ रहे हैं। वे आर्थिक रूप से मजबूत होकर आज अपने व्यवसाय के माध्यम से 6-7 लोगों को भी रोजगार देने में सक्षम हुए हैं। लाभार्थी

राहुल ने इस योजना को सराहा है, उन्होंने कहा है कि, पशुपालन विभाग की योजनाओं के माध्यम से पशुपालकों एवं किसानों को काफी फायदा पहुंच रहा है। मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना के तहत लाभार्थी को करनाल, हरियाणा से लाई गई दो मुर्ग भैंस प्रदान की गई है। राहुल खेती-बाड़ी का कार्य भी करते हैं, वे बताते हैं कि, पशुपालन से उन्हें कृषि कार्य में मदद मिली है। अब वे रसायनिक खादों की बजाय गोबर खाद का इस्तेमाल अपने खेतों में करते हैं, उससे मिट्टी की उर्वरता तो बढ़ती ही है और उन्हें अच्छे उत्पाद भी प्राप्त हो रहे हैं। इस योजना से अप्रत्यक्ष रूप से जैविक खेती को भी बढ़ावा मिल रहा है। इसके अलावा राहुल अन्य पशुओं जिसमें 500 बकरियों और गाय का भी पालन करते हैं। राहुल आज एक सफल पशुपालक के तौर पर जाने जाते हैं, उनकी कहानी अन्य किसानों के लिए एक प्रेरणा है। वे दूसरे किसानों से कहते हैं कि, वे ज्यादा से ज्यादा पशुपालन करें, इससे हमारी आय में वृद्धि और कृषि कार्य में सहयोग मिलता है।

बुरहानपुर (कृषक जगत)। बुरहानपुर जिले में मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। पशुपालन विभाग के तहत संचालित इस योजना में जिले के 10 हितग्राहियों को 2-2 मुर्ग भैंस प्रदान की गई हैं। जिले के ग्राम इच्छापुर के पशुपालक श्री राहुल चौहान लाभान्वित हुए हैं। राहुल, सरकारी योजनाओं की मदद से अपने पशुपालन व्यवसाय को बढ़ाकर तरक्की की ओर बढ़ रहे हैं।

मध्यप्रदेश सरकार की "मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना" पशुपालन को बढ़ावा देकर किसानों और पशुपालकों की आय बढ़ाने में कारगर है। यह योजना स्वरोजगार के अवसर पैदा करने और राज्य को दूध उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए शुरू की गई है। इस योजना के तहत पशुपालकों को दुधारू पशु खरीदने के लिए 50 से 75 प्रतिशत तक की सब्सिडी प्रदान की जाती है। जिसमें सामान्य/अन्य पिछड़ा वर्ग को 50 प्रतिशत व अनुसूचित जाति/जनजाति को 75 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है। मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना अंतर्गत पशुपालकों को दो मुर्ग भैंसें

बारिश की चिंता और खेती का फैसला
 खेती में सबसे बड़ी चिंता हमेशा यही रहती है कि बारिश कब होगी और कितनी होगी। खासकर खरीफ की खेती तो पूरी तरह मानसून पर निर्भर करती है। अगर किसान को समय से पहले पता चल जाए कि मानसून कब आएगा, तो वह यह तय कर सकता है कि कौन-सी फसल बोनी है, कितनी बोनी है और कब बोनी है।

अब एआई से पहले ही मिलेगी खबर
 इस साल भारत सरकार ने किसानों के लिए एक बड़ी पहल की है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) से बने मौसम पूर्वानुमान को सीधे किसानों तक पहुँचाया गया। कृषि मंत्रालय ने m-Kisan पोर्टल के जरिए 13 राज्यों के लगभग 3.8 करोड़ किसानों को SMS भेजे। खास बात यह रही कि यह जानकारी मानसून आने से करीब चार हफ्ते पहले ही दी गई। यानी किसान पहले से ही खरीफ की योजना बना सके।

समय पर मदद, सही फैसला
 मानसून इस बार जल्दी आ गया, लेकिन बीच में करीब 20 दिन तक बारिश थम गई। ऐसी स्थिति में किसानों को सबसे ज्यादा परेशानी होती है। लेकिन एआई आधारित पूर्वानुमान ने इस रुकावट को समय पर पहचान लिया। सरकार ने हर हफ्ते किसानों को अपडेट भेजे और लगातार जानकारी दी, जब तक कि उनके क्षेत्र में अच्छी बारिश शुरू नहीं हो गई।

मौसम पूर्वानुमान में क्रांति
 एआई ने मौसम की भविष्यवाणी को नई दिशा

भारत का एआई आधारित मौसम पूर्वानुमान

किसानों के लिए नई उम्मीद



दी है। साल 2022 से इसका इस्तेमाल शुरू हुआ

और अब यह तकनीक किसानों के लिए किसी

वरदान की तरह है। गूगल का Neural GCM मॉडल और यूरोप का Artificial Intelligence Forecasting System (AIFS), दोनों ने पारंपरिक पूर्वानुमानों से कहीं बेहतर प्रदर्शन किया और मानसून की सही शुरुआत का पता लगाया।

किसानों की भाषा में संदेश

इस पूरी प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण यह रहा कि किसानों को भेजे गए संदेश आसान भाषा में थे। उन्हें तकनीकी शब्दों के बजाय सीधे-सीधे बताया गया कि क्या करना है—बीज डालना है, इंतजार करना है या सिंचाई की तैयारी करनी है। इससे किसान बिना किसी उलझन के तुरंत निर्णय ले पाए।

विशेषज्ञों की राय

कृषि मंत्रालय के संयुक्त सचिव संजय कुमार अग्रवाल का कहना है कि जलवायु परिवर्तन से मौसम की अनिश्चितता बढ़ी है और एआई किसानों को बदलते हालात में ढलने में मदद करेगा। नीति आयोग के सदस्य प्रोफेसर रमेश चंद ने इसे किसानों के लिए बेहद अहम पहल बताया। वहीं नोबेल पुरस्कार विजेता माइकल क्रेमर ने कहा कि भारत ने करोड़ों किसानों तक एआई का लाभ पहुँचाकर दुनिया को एक नई दिशा दिखाई है।

किसानों के लिए नया भरोसा

कुल मिलाकर, अब किसान अटकलबाजी के बजाय एआई की सटीक जानकारी पर भरोसा कर सकेंगे। यह पहल खेती को और सुरक्षित, समझदार और फायदेमंद बनाएगी। किसानों के लिए यह एक नया भरोसा है—अब मानसून की बारिश कब होगी, इसकी खबर उन्हें पहले से मिल जाएगी।

तारीफ यही है कि वे 'ताहिर भाई' हैं

जनसम्पर्क शैली ने बनाई पत्रकारों, राजनेताओं और प्रशासन में पहचान



● सुरेश गुप्ता
पूर्व अपर संचालक,
जनसंपर्क

सैयद ताहिर अली संक्षेप में एस टी ए 3 अक्टूबर को 71 वर्ष पूरे कर 72वें वर्ष में प्रवेश कर गए हैं। प्रसंग जन्म-दिवस का है तो मित्र और सहकर्मियों द्वारा बधाई और शुभकामनाएँ देने के साथ ही व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में भी बात की जाना चाहिये। जनसम्पर्क विभाग में ताहिर भाई ने विभिन्न पदों पर रहकर संयुक्त संचालक के पद से सेवानिवृत्ति तक 34 वर्ष बिताये। उनके सेवाकाल, जनसम्पर्क अधिकारी के रूप में उनकी दक्षता, कार्य-कुशलता के बारे में बात करने से पहले व्यक्ति ताहिर भाई को जान लें। 3 अक्टूबर, 1954 को भोपाल में उच्च शिक्षित और संस्कारित परिवार में जन्में ताहिर भाई ने विनम्र, सौम्य और व्यवहार कुशल व्यक्ति के रूप में जो पहचान बनायी है, वह बहुत कम लोगों को नसीब होती है। वे गंगा-जमुनी तहजीब को जीते रहे हैं और जी रहे हैं। अपनी इस पहचान और गुण से उन्होंने शासकीय जनसम्पर्क जैसे जटिल और दुरुह कार्य को भी इतना आसान बना लिया कि देखते ही बनता है। शायद ही कभी ऐसा हुआ होगा कि वे अपने जनसम्पर्कीय दायित्व

के निर्वहन में (संकटकाल में भी) सफल नहीं रहे हों। नये जनसम्पर्क अधिकारी उनसे व्यवहार कुशलता और मीडियाकर्मियों से स्नेही संबंध तो सीख ही सकते हैं। कभी-कभी अकेले व्यवहार कुशलता और मृदुभाषी होना आपको हँसी का पात्र भी बना देता है परंतु ताहिर भाई के साथ ऐसा नहीं हुआ तो वह इसलिये कि

संबंधों के निर्वहन में भी उनका कोई सानी नहीं है। दो-तीन उदाहरणों से इसे समझा जा सकता है— वे सन् 1987 में छिंदवाड़ा में जिला जनसम्पर्क अधिकारी थे, कलेक्टर थे आईएएस श्री अंतोनी डिसा। सभी पीआरओ के कलेक्टर से अच्छे संबंध बन जाते हैं खासतौर से उनके जो जरा से भी काबिल हों। ताहिर भाई के श्री डिसा से संबंध उनके मुख्य सचिव बल्कि रेरा चेयरमैन बनने तक बरकरार रहे और आज भी हैं। कई और वरिष्ठ आईएएस से उनके साथ काम करने की वजह से ताहिर भाई के आत्मीय संबंध हैं। भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त श्री ओ.पी. रावत से भी संबंध और सम्पर्क बरकरार हैं। दूसरा जो मुझे याद आता है लंबे समय से प्रदेश मंत्री-मण्डल के कई वरिष्ठ मंत्रियों के साथ

उन्होंने काम किया जो उनसे जुड़े रहे। वर्तमान उप मुख्यमंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल तक (जिनके साथ वे सेवानिवृत्ति के बाद भी उनके मीडिया सलाहकार के रूप में कार्य कर रहे हैं), ये शृंखला जो 21 वर्ष है और बहुत लम्बी और संबंधों के निर्वहन की मिसाल भी है। ताहिर भाई एक बार जिसके हो गये तो हो गये फिर वे पूरे तन-मन-कर्म से उसके साथ हैं। आज कई तरह के इन्फ्लुएंसर विचरण कर रहे हैं पर मेरे मत में ताहिर भाई के आगे सब फीके हैं। उनके सामाजिक, राजनैतिक, शासकीय सम्पर्कों का इन्फ्लुएंसर उनके साथ रहकर, उनके साथ काम



करते हुए या उन्हें काम सौंपकर ही जाना जा सकता है। कहा तो यह भी जाता है कि उन्हें काम सौंपकर निश्चित हुआ जा सकता है। एक हद तक यह सही भी है। ताहिर भाई शासकीय सेवा से पहले क्या ओढ़ते-बिछाते थे, पता नहीं। शायद आम इंसानों की तरह चादर-रजाई ओढ़ते होंगे और सोने के लिये दरी-गद्दा बिछाते होंगे पर शासकीय सेवा में वे अपने काम को ही ओढ़ते-बिछाते रहे हैं,

जिसका लाभ उन्हें कुशल जनसम्पर्क अधिकारी के तमगे के रूप में मिला है। वे परिश्रमी हैं तो कार्य-कुशल भी, कर्मठता को उन्होंने जिया है और जी रहे हैं। यह सही है कि ताहिर भाई आज दक्ष जनसम्पर्क अधिकारी माने जाते हैं और हैं भी। परंतु हमेशा ऐसा नहीं था, तो फिर सवाल उठता है कि फिर वे

इतने लोकप्रिय और दक्ष कैसे हो गये। इसका जवाब है उनकी सीखने की, सहयोग लेने की, हमेशा अपने को एक पायदान नीचे रखकर, एक पायदान ऊँचे परिणाम देने की मनोवृत्ति। अच्छा काम करने, अच्छे परिणाम प्राप्त करने में सबका सहयोग लेने और सहयोग करने वाले का अकेले में नहीं हर उपयुक्त जगह और समय पर आधारित जताने में ताहिर भाई ने कभी गुरेज नहीं किया। यही गुण उन्हें बड़ा और बिरला बनाता है। वे सीखकर अपना आज बना पाये हैं, विरासत से नहीं। पत्रकार भाइयों से आत्मीय संबंध रखने वाले ताहिर भाई यारबाज हैं, पुरलुफ्त हैं और हैं खुशदिल। शायद ही वे कभी उदास होते हों। यारबाजी तो कोई उनसे सीखे। साथ ही हिन्दू-मुस्लिम सभी त्यौहारों का, मांगलिक अवसरों का (घर-परिवार के साथ ही अपने नियर-डीयर) का जैसा लुत्फ वे लेते हैं, लुत्फ दिलाते हैं, बहुत कम लोग कर पाते हैं। अब तो अपने इकलौते पुत्र आसिम को भी उन्होंने अपनी इस रवायत का वारिस बना लिया है। अब जरा ताहिर भाई की पारिवारिक पृष्ठभूमि की बात कर लें, तो जनाब मशहूर शिक्षाविद् और इतिहासकार मरहूम डॉ. सैयद अशफाक अली के चश्म-ओ-चिराग हैं। वहीं डॉ. अशफाक अली जो सेफिया कॉलेज के उरुज के समय 18 वर्ष कॉलेज के प्रिंसिपल रहे। उन्होंने भोपाल के इतिहास का सबसे पहला दस्तावेजीकरण Bhopal Past and Present लिखकर किया। ताहिर भाई ने जिस तरह विरासत और वर्तमान को साधा है, वह उन्हें नेकनीयत, पुरलुत्फ और यारबाज बनाने में मददगार रहा है और रहेगा। वे दीर्घायु हों, यही कामना है। भोपाल आज नहीं तो कल जरूर उन्हें अपने मरकज का हीरा मानेगा, इसी उम्मीद के साथ। अंत में तारीफ यही है कि वे ताहिर भाई हैं।

रबी में कृषि पंप के लिए किसान निर्धारित दरों के अनुसार ही भुगतान करें

भोपाल (कृषक जगत)। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा कंपनी कार्यक्षेत्र के भोपाल, नर्मदापुरम, चंबल एवं ग्वालियर संभाग के 16 जिलों के अंतर्गत कृषि उपभोक्ताओं को रबी सीजन में निर्बाध एवं गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति प्रदान करने के लिए अस्थाई कृषि पम्प कनेक्शन प्रदान करने की माकूल व्यवस्था की है।

गौरतलब है कि ग्रामीण क्षेत्र के कृषि उपभोक्ताओं को राज्य शासन द्वारा दी जा रही सब्सिडी घटाने के बाद श्री फेज तीन हॉर्स पावर के अस्थाई पम्प कनेक्शन के लिए तीन माह के लिये कुल राशि रु. 5 हजार 917, चार माह के लिये रु. 7 हजार 775 एवं पांच माह के लिये 9 हजार 634 रुपये देय होंगे तथा पांच हॉर्स पावर अस्थाई पम्प कनेक्शन

के लिए तीन माह के लिये रु. 9 हजार 634, चार माह के लिये रु. 12 हजार 732 एवं पांच माह के लिये 15 हजार 831 रुपये तथा



साढ़े सात से आठ हॉर्स पावर अस्थाई पम्प कनेक्शन के लिए तीन माह के लिये रु. 15 हजार 211, चार माह के लिये रु. 20 हजार 168 एवं पांच माह के लिये 25 हजार 125

रुपये देय होंगे। श्री फेज दस हॉर्स पावर अस्थाई पम्प कनेक्शन के लिए ग्रामीण क्षेत्र के कृषि उपभोक्ताओं को तीन माह के लिये 18 हजार 929 रुपये, चार माह के लिये 25 हजार 125 रुपये एवं पांच माह के लिये 31 हजार 321 रुपये देय होंगे।

कंपनी ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र के कृषि उपभोक्ताओं के लिये अस्थाई पम्प कनेक्शन की दरें 8 अप्रैल 2025 से लागू हैं और उपभोक्ताओं को इन्हीं दरों पर अस्थाई पम्प कनेक्शन प्रदाय किये जा रहे हैं। कंपनी ने बताया है कि उचित रेटिंग का कैपेसिटर लगा होने पर कैपेसिटर सरचार्ज देय नहीं होगा एवं उपभोक्ताओं को अस्थाई पम्प कनेक्शन के लिये न्यूनतम तीन माह का अग्रिम भुगतान अनिवार्य होगा।

समर्थन मूल्य पर धान, ज्वार एवं बाजरा उपार्जन के लिए पंजीयन 10 अक्टूबर तक



भोपाल (कृषक जगत)। खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में समर्थन मूल्य पर धान, ज्वार एवं बाजरा उपार्जन के लिये किसान पंजीयन प्रक्रिया का निर्धारण कर दिया गया है। किसान 10 अक्टूबर तक पंजीयन करा सकते हैं। पंजीयन 15

सितम्बर से शुरू हो चुका है। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत ने किसानों से आग्रह किया है कि निर्धारित समय में पंजीयन करा लें, जिससे किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं हो। उन्होंने बताया है कि किसान पंजीयन की व्यवस्था को सुगम बनाया गया है। प्रदेश में 1255 पंजीयन केन्द्र बनाये गये हैं।

पंजीयन की निःशुल्क व्यवस्था

पंजीयन की निःशुल्क व्यवस्था ग्राम पंचायत और जनपद पंचायत एवं तहसील कार्यालयों में स्थापित सुविधा केन्द्र पर सहकारी समितियों एवं सहकारी विपणन संस्थाओं द्वारा संचालित पंजीयन केन्द्र पर तथा एम.पी. किसान एप पर भी की गई है।

पंजीयन की सशुल्क व्यवस्था

पंजीयन की सशुल्क व्यवस्था एम.पी.

ऑनलाईन कियोस्क, कॉमन सर्विस सेन्टर कियोस्क, लोक सेवा केन्द्र और निजी व्यक्तियों द्वारा संचालित साइबर कैफे पर की गई है। प्रति पंजीयन के लिये 50 रुपये से अधिक शुल्क नहीं लिया जाएगा।

भुगतान के लिए बैंक खाता

किसान द्वारा समर्थन मूल्य पर विक्रय उपज का भुगतान प्राथमिकता के आधार पर किसान के आधार लिंक बैंक खाते में किया

जाएगा। किसान पंजीयन के समय किसान को बैंक खाता नंबर और IFSC कोड की जानकारी उपलब्ध करानी होगी।

सभी जिला कलेक्टर को निर्देशित किया गया है कि जिला और तहसील स्तर पर स्थापित आधार पंजीयन केन्द्रों को क्रियाशील रखा जाए जिससे किसान वहां जाकर आसानी से अपना मोबाइल नंबर एवं बायोमेट्रिक अपडेट करा सके।

किसान का पंजीयन केवल उसी स्थिति में हो सकेगा जबकि किसान के भू-अभिलेख के खाते एवं खसरे में दर्ज नाम का मिलान आधार कार्ड में दर्ज नाम से होगा। भू-अभिलेख और आधार कार्ड में दर्ज नाम में विसंगति होने पर पंजीयन का सत्यापन तहसील कार्यालय से कराया जाएगा। सत्यापन होने की स्थिति में ही उक्त पंजीयन मान्य होगा।

फोटो - गैलरी



चेटबॉट लांच

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने विजयादशमी पर नागरिकों की सुरक्षा के लिए इंदौर पुलिस द्वारा तैयार किये गए एआई बेस्ड चेटबॉट सेफ क्लिक को लांच किया। कार्यक्रम में सांसद श्री शंकर लालवानी, महापौर श्री पुष्पमित्र भार्गव, संभागायुक्त डॉ. सुदाम खाड़े, पुलिस कमिश्नर श्री संतोष कुमार सिंह, कलेक्टर श्री शिवम वर्मा सहित अनेक जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।



सौजन्य भेंट

गत दिनों रूस के उप प्रधानमंत्री श्री दिमित्री पेनुशेव, उनके डिप्टी एग्रीकल्चर मिनिस्टर सहित प्रतिनिधिमंडल के साथ केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की नई दिल्ली में उच्चस्तरीय बैठक हुई। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि रूस के समर्थन व सहयोग से व्यापार और लंबित मुद्दों का निश्चित तौर पर समाधान निकलेगा, जिसका लाभ हमारे किसानों, उपभोक्ताओं एवं दोनों देशों के नागरिकों को मिलेगा।



कॉन्फ्रेंस

उप मुख्यमंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने कहा कि संभागीय बैठकें जिलों के विकास में तेजी ला रही हैं। बैठक में अपर मुख्य सचिव श्रीमती रश्मि अरुण शर्मा भी उपस्थित थीं।

सोलर प्लस स्टोरेज मुरैना एक ऐतिहासिक परियोजना : श्री शुक्ला

अब तक का न्यूनतम रुपये 2.70 प्रति यूनिट का टैरिफ

भोपाल (कृषक जगत)। नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री राकेश शुक्ला ने कहा है कि सोलर प्लस स्टोरेज मुरैना परियोजना ऐतिहासिक है। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश मुरैना में अपनी पहली सोलर प्लस स्टोरेज परियोजना विकसित कर रहा है, जिसमें रु 2.70 प्रति यूनिट का ऐतिहासिक टैरिफ प्राप्त हुआ है। यह भारत में पहली बार है कि किसी फर्म और डिसपेचेबल रिएन्यूबल एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए रु 3 प्रति यूनिट से कम टैरिफ हासिल किया गया है। श्री शुक्ला ने इस बात पर संतोष जताया गया कि परियोजना में प्राप्त न्यूनतम टैरिफ प्रदर्शित करता है कि नवकरणीय ऊर्जा भी डिस्कॉम के लिए अधिक किफायती हो सकती है। कांफ्रेंस में अपर मुख्य सचिव ऊर्जा श्री मनोज श्रीवास्तव एवं ऊर्जा विकास निगम के प्रबंध संचालक श्री अमनवीर सिंह बैस भी उपस्थित थे।

श्री शुक्ला ने कहा कि सोलर स्टोरेज प्रोजेक्ट मुरैना की विशेषता है कि इसके द्वारा सामान्य सौर घंटों एवं पीक घंटों के दौरान समान स्तर की

विद्युत आपूर्ति की जाएगी। देश की पहली सोलर प्लस स्टोरेज परियोजना है, जिसमें 95 प्रतिशत पीक आपूर्ति की सुनिश्चित वार्षिक उपलब्धता है। साथ



ही टैरिफ भी न्यूनतम 2.70 प्रति यूनिट है। अब तक सबसे कम टैरिफ रु 3.09 प्राप्त हुआ था, जो शाम को 2 पीक ऑवर्स में अनुबंधित सौर क्षमता के केवल 50 प्रतिशत की आपूर्ति एवं 85 प्रतिशत वार्षिक उपलब्धता के लिये

था। श्री शुक्ला ने बताया कि विगत 19 सितंबर, 2025 को हुई ई-रिवर्स नीलामी में प्राप्त दर आगामी 25 वर्षों के लिए निर्धारित हुई है। यह रु. 2.70 प्रति kWh के ऐतिहासिक टैरिफ के

साथ संपन्न हुई है। यह पूरे भारत में FDRE निविदाओं के लिए एक मील का पत्थर है। निविदा में 16 बोलीदाताओं के साथ वैश्विक भागीदारी देखी गई, जिसमें बोली क्षमता की खरीद की जाने वाली बोली क्षमता का लगभग 10 गुना था। नीलामी में एकमे सोलर होल्डिंग्स, अदानी रिन्यूएबल, एम्पिन एनर्जी, अप्रावा एनर्जी, सीगल इंडिया लिमिटेड, दिलीप बिल्डकॉन, एंजी एनर्जी, गोल्डी सोलर, एमबी पावर, एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी, पावर मेक, पूर्वा ग्रीन, रिन्यू सोलर, सेरेंटिका रिन्यूएबल्स, शिवालय कंस्ट्रक्शन्स और वारी फॉरएवर एनर्जीज सहित प्रतिष्ठित कंपनियां शामिल रही।

देपालपुर में अतिवृष्टि से सोयाबीन को नुकसान

(शैलेश ठाकुर, देपालपुर, कृषक जगत)। क्षेत्र के सोयाबीन किसानों की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। एक ओर अतिवृष्टि ने सोयाबीन फसल को नुकसान पहुंचाया है, वहीं दूसरी ओर किसानों को सोयाबीन फसल का उचित दाम भी नहीं मिल रहा है। इसे लेकर क्षेत्र के किसानों ने अपनी पीड़ा कृषक जगत से साझा की।

बता दें कि इस वर्ष देपालपुर क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होने से खेतों में पानी भर गया है। जलभराव होने से सोयाबीन के पौधों में गलन शुरू होने तथा दाना भी खराब होने से उत्पादन की गुणवत्ता भी प्रभावित हो रही है। इससे दाम कम मिलने की आशंका है। गांवों में खेतों तक पहुंचने वाले कच्चे रास्ते भी कीचड़ में

बदल गए हैं। ट्रैक्टर और वाहन फंस रहे हैं, जिससे किसानों को खेतों तक पहुंचना मुश्किल हो गया है। हालांकि सरकार ने भावान्तर योजना लागू करने

खराब हुआ है। फसल कटाई में भी देरी हो रही है। बिरगोदा के श्री पवन सोनगरा ने बताया कि सोयाबीन की फलियां सड़ और गल रही है।

सोयाबीन पक गई है लेकिन खेतों में पानी भरा होने से अभी थ्रेसर, ट्रैक्टर और हार्वेस्टर खेतों में नहीं जा पा रहे हैं। बोरिया के श्री राहुल मकवाना की सोयाबीन की अगेती और पछेती दोनों किस्में ज्यादा जल भराव के कारण सड़ने लगी है। चांदेर के श्री राहुल केलवा ने कहा कि तालाब और नदी के पास वाले खेतों में जल भराव को लेकर सीएम हेल्पलाइन पर भी शिकायत दर्ज की थी। बीमा हेल्पलाइन पर भी सूचना देने हेतु कॉल लगाया था, लेकिन नहीं लगा। देपालपुर क्षेत्र के सभी किसान परेशान हैं।



की घोषणा की है, लेकिन सोयाबीन की गुणवत्ता खराब होने से किसानों को अधिक लाभ नहीं मिल पाएगा। सनावदा के श्री नारायण पवार ने कृषक जगत को बताया कि क्षेत्र में ज्यादा बारिश से सोयाबीन का दाना

केवीके खरगोन में हुई 'कलम बंद हड़ताल'

(दिलीप दसौंधी, मंडलेश्वर, कृषक जगत)। फोरम ऑफ केवीके एंड एआईसीआरपी के राष्ट्रीय आह्वान के अनुरूप, कृषि विज्ञान केंद्र (केवीके), खरगोन के वैज्ञानिकों/कर्मचारियों ने 'कलम बंद हड़ताल' की। यह आंदोलन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) की भेदभावपूर्ण नीतियों के विरोध में और 'वन नेशन, वन केवीके, वन पॉलिसी' की माँग को लेकर था। प्रदर्शन के दौरान केंद्र पर बैनर और प्लेकार्ड्स के माध्यम से अपनी माँगों को रखा और 'हमें चाहिए न्याय', 'वन नेशन-वन केवीके-वन पॉलिसी' जैसे नारों के साथ आईसीएआर की भेदभावपूर्ण रवैये के खिलाफ आवाज बुलंद की।

केवीके खरगोन प्रतिनिधि ने बताया कि यह विरोध केवल वेतन की बात नहीं, बल्कि सम्मान और समान अधिकारों की लड़ाई है। 'हम आईसीएआर के अधीन काम करने वाले

अपने सहयोगियों के समान ही जिम्मेदारी निभाते हैं, लेकिन वेतन, पदोन्नति, भत्तों और सेवानिवृत्ति लाभों में हमें लगातार दायम दर्जे का व्यवहार झेलना पड़ रहा है। यह अन्यायपूर्ण है और इसे तुरंत समाप्त किया जाना चाहिए।' पूर्व में भी



केवीके फोरम एवं एआईसीआरपी द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर किए गए आंदोलन जिस पर आईसीएआर ने आश्वासन दिया था कि हम अगले 100 दिन में आपकी सभी समस्याओं को दूर कर देंगे लेकिन आज तक हमारी समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं। केवीके खरगोन के कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी माँगों पर शीघ्र ध्यान नहीं दिया गया, तो वे आगामी रबी अभियान का पूर्ण बहिष्कार करेंगे।

नरवाई प्रबंधन पर कार्यशाला आयोजित



नर्मदापुरम (कृषक जगत)। जिला पंचायत नर्मदापुरम के सभाकक्ष में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत नर्मदापुरम श्री सौजन सिंह रावत की अध्यक्षता में जिले में नरवाई प्रबंधन विषय पर कार्यशाला संपन्न हुई। कार्यशाला में जिलों के सातों विकासखंड से हार्वेस्टर एजेंट तथा कृषक सम्मिलित हुए।

श्री रावत ने नरवाई जलाने से खेतों में होने वाले दुष्परिणामों के संबंध में अवगत कराते हुए कहा कि इससे मृदा में उपस्थित लाभकारी कीट एवं बैक्टीरिया के साथ-साथ जीवाश्म पदार्थ जलकर नष्ट हो जाते हैं। जिससे फसलों की उत्पादन एवं उत्पादकता कम हो रही है। जिसको बनाए रखने के

लिए किसानों को अधिक यूरिया एवं डीएपी का प्रयोग करना पड़ता है। इससे मिट्टी की उपजाऊ क्षमता कम हो रही है एवं आग लगने से मिट्टी कठोर हो रही है।

उप संचालक, कृषि श्री जे. आर. हेड़ाऊ ने बताया कि नरवाई से होने वाली घटनाओं में संपूर्ण मध्यप्रदेश में नर्मदापुरम जिला अग्रणी श्रेणी में आता है। इसलिए हार्वेस्टर एजेंट एवं किसानों का दायित्व बढ़ गया है। श्री हेड़ाऊ ने सलाह दी कि धान की कटाई के समय हार्वेस्टर मशीन के साथ स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम अथवा मल्चर का प्रयोग करें, जिससे खेतों में नरवाई पूर्णतः समाप्त हो जाती है। प्रयोगशाला में उपस्थित सहायक संचालक,

कृषि श्री शैलेन्द्र राठौर ने चर्चा के दौरान बताया कि फसल कटाई उपरांत कृषक सीधे सुपरसीडर या स्मार्टसीडर चलाकर अगली फसल की बुवाई कर सकते हैं एवं नरवाई जलने के नकारात्मक प्रभावों से बच सकते हैं।

सहायक कृषि यंत्री श्री चंदन सिंह बरकड़े ने कार्यशाला में उपस्थित हार्वेस्टर एजेंट एवं बड़े कृषकों से अपील की जिले में पर्याप्त मात्रा में नरवाई प्रबंधन यंत्र के लक्ष्य अनुदान पर उपलब्ध है एवं नरवाई प्रबंधन के यंत्रों में लॉटरी सिस्टम नहीं अपनाया जाता। कृषकों के आवेदन अनुसार प्रकरण स्वीकृत कर दिए जाते हैं। उन्होंने सभी किसान भाइयों से अपील की कार्यालय सहायक कृषि यंत्री, पवारखेड़ा जिला नर्मदापुरम में संपर्क कर अधिक से अधिक आवेदन करें। कार्यशाला में लगभग 50 से अधिक हार्वेस्टर एजेंट एवं बड़ी संख्या में कृषकगण उपस्थित थे।

फसलों की नई किस्मों को कृषकों के बीच लाया जाए : डॉ. श्रीवास्तव



देवास (कृषक जगत)। कृषि विज्ञान केंद्र, देवास द्वारा 36वीं वैज्ञानिक सलाहकार समिति की बैठक का आयोजन हाइब्रिड माध्यम से किया गया। उक्त कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डॉ. एस.आर.के. सिंह, निदेशक, अटारी, जबलपुर, के प्रतिनिधि डॉ. रजनीश श्रीवास्तव, अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, इंदौर की प्रतिनिधि डॉ. दीक्षा टेंबरे के साथ-साथ कृषि विज्ञान केंद्र, शाजापुर एवं इंदौर से क्रमशः डॉ. मुकेश सिंह व डॉ. डी.के.मिश्रा द्वारा ऑनलाइन जुड़कर भागीदारी की गई।

इस बैठक में जिले के कृषि संबद्ध विभागों के प्रमुख श्री राजू बड़वाया, उप-संचालक, उद्यानिकी, उप-संचालक कृषि के प्रतिनिधि श्री विलास पाटिल, डॉ. एस.के. श्रीवास्तव, उप-संचालक, पशुपालन विभाग, श्री गोविन्द दांगी, मत्स्य विभाग, श्री बी.एस.दलोदिया, कृषि अभियांत्रिकी, श्री राजेश पाटीदार, इफको, श्री जयप्रकाश पाटीदार, कृषको, श्री राजेश भट्ट, बीज निगम, श्री रामवीर

किरार, सचिव, कृषि उपज मंडी के साथ-साथ जिले के विभिन्न कृषक उत्पादन संगठन एवं गैर-शासकीय संस्थाओं के प्रतिनिधि एवं प्रगतिशील कृषक व कृषक महिलाएं उपस्थित थीं।

बैठक में प्रधान वैज्ञानिक एवं प्रमुख डॉ. आर.पी. शर्मा ने कार्यक्रम के उद्देश्य के बारे में एवं डॉ. के. एस.भार्गव, वरिष्ठ वैज्ञानिक द्वारा गतिविधियों का प्रगति प्रतिवेदन एवं प्रस्तावित कार्ययोजना के बारे में प्रस्तुतिकरण दिया गया। निदेशक, अटारी प्रतिनिधि डॉ. रजनीश श्रीवास्तव ने कहा कि फसलों की नई किस्मों को कृषकों के बीच लाया जाए। अधिष्ठाता प्रतिनिधि डॉ. दीक्षा टेंबरे ने कहा सब्जियों में प्राकृतिक खेती के मॉडल कृषि विज्ञान केंद्र में डाले जाए। श्री विलास पाटिल, सहायक उप-संचालक ने प्राकृतिक खेती से संबंधित प्रदर्शन डाले जाने के बारे में सुझाव दिया। श्री राजू बड़वाया, सहायक उप-संचालक, उद्यानिकी बीमारियों के प्रबंधन का सुझाव दिया।

धान फसल में यूरिया के प्रयोग से बचने की सलाह

सतना (कृषक जगत)। उप संचालक कृषि श्री आशीष पाण्डेय ने किसानों को सलाह दी है कि वर्तमान में धान की फसल में बालियां निकलना प्रारंभ हो गई हैं। ऐसी स्थिति में यूरिया का छिड़काव फसल के लिये हानिकारक है। धान की फसल में यूरिया के प्रयोग से बचें। इस समय यूरिया का छिड़काव करने से बालियां फफूंद जनित रोगों के



प्रति संवेदनशील हो जाती हैं। जिससे है। इसके बजाय इस समय बालियों के विकास के लिए अ। व श य क पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए पोटाश व फास्फोरस आधारित उर्वरकों का

प्रयोग करना चाहिए। बालियों के विकास और दाने बनने की अवस्था में फसल को पर्याप्त नमी देना भी जरूरी होता है। लेकिन यूरिया से बचना चाहिए। आगामी रबी सीजन के लिये अभी यूरिया का भण्डारण न करें क्योंकि इसे लम्बे समय तक रखने से नमी एवं अधिक ताप के कारण नाइट्रोजन नष्ट हो जाता है एवं यूरिया उर्वरक गुणवत्ता विहीन हो जाता है।

समस्या-समाधान

समस्या— सर्पगन्धा की खेती में इच्छुक हूँ, परामर्श देने की कृपा करें।

— अम्बिका पटेल

समाधान— सर्पगन्धा की खेती के लिये नम



तथा हल्के गर्म मौसम की आवश्यकता होती है।

● इसकी जड़ें औषधि के रूप में उपयोग में आती हैं।

● अच्छे निकास वाली बलुई से भारी दोमट मिट्टी जिसका पी.एच. 8 से कम हो उपयुक्त रहता है। 4.6 से 6.2 पी.एच. अधिक उपयुक्त।

● धूप व आंशिक छाया वाले खेत अधिक उपयुक्त जहां पाला पड़ता हो वहां न लगायें।

● 25 से 30 टन गोबर की अच्छी सड़ी खाद अवश्य डालें।

जाति—सर्पगन्धा— 1, (कृषि महाविद्यालय, इंदौर में विकसित)।

● उत्पत्ति— बीज, जड़ों व तनों से।

● बीज बोने का समय— मई मध्य, 6 माह से पुराने बीज का अंकुरण 15-20 दिन बाद।

● बीज नर्सरी में बोयें। एक हेक्टर के लिए 500 वर्ग मीटर नर्सरी लगायें, बीज मात्रा 5.5 किलोग्राम।

● रोपड़ 4-6 अवस्था में, मुख्य जड़ काट कर।

● जड़ों से बुआई— मार्च से जून तक 100 किलोग्राम जड़ें (10-12 से.मी.) प्रति हेक्टर।

● उपज— 25 क्विंटल जड़ें प्रति हेक्टर 18 माह में।

समस्या— गेहूं में पहली बार नींदा नियंत्रण के लिए नींदानाशक का प्रयोग करना चाहता हूँ, परामर्श दीजिए।

— संदीप साय

समाधान— ● गेहूं में दोनों सकरी तथा चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार/ नींदा आते हैं।

● संकरी पत्ती वाले नींदा में जंगली जई, चिरैया बाजरा, दूब व कांस प्रमुख हैं। चौड़ी पत्ती में बथुआ, दूधी, हिरनखुरी, कटेली, सेजी,

कृष्णनील, अकरी आदि प्रमुख हैं।

● आपके खेत में कौन-कौन से नींदा की बहुलता है। उस आधार पर नींदानाशक का चयन करना होगा।

● यदि दोनों प्रकार के नींदा आपके गेहूं के खेतों में आते हैं तो पेन्डामेथिन 30 ईसी के 3.3 लीटर को 500-600 लीटर पानी में घोल कर बुआई के तुरन्त बाद से 3 दिन के अंदर से छिड़काव करें। यह संकरी तथा चौड़ी दोनों प्रकार की नींदा को नियंत्रित करेगा।

● यदि आपकी फसल में संकरी पत्ती वाले नींदा हो तो आइसोप्रोटूरॉन 75 की एक किलो ग्राम— 500-600 लीटर पानी में मिलाकर छिड़कें।

● यदि दोनों प्रकार के नींदा आते हो तो आइसोप्रोटूरॉन में 250 ग्राम 2-4 डी सोडियम लवण 30 प्रतिशत मिलाकर बुआई के 30 दिन के अंदर छिड़कें। इसके अतिरिक्त सल्फोसल्फूरॉन 25 ग्राम प्रति हेक्टर का भी उपयोग किया जा सकता है।

नींदानाशक के उपयोग में निम्न सावधानी अवश्य रखें।

● छिड़कते समय भूमि में पर्याप्त नमी अवश्य रहे।

● प्लेट फेन या प्लेट जेट नोजल का ही प्रयोग करें।

● स्प्रे पूरे क्षेत्र में अच्छी तरह व एक समान हो।

● स्प्रे खुले सूखे मौसम में करें।

समस्या— गेहूं की फसल में दीमक बहुत नुकसान पहुंचाती है। रोकथाम के उपाय बतायें।

— सुरेश कुमार

समाधान— ● खेत के आसपास दीमक के बमीठों को खोदकर रानी दीमक को नष्ट करने का प्रयत्न करें। पूरे गांव में सामूहिक रूप से यह



कार्य किया जाये तो अच्छे व दूरगामी परिणाम मिलेंगे।

● गेहूं बोने के पूर्व बीज को क्लोरोफायरीफॉस 20 ई.सी. के 5 मि.ली. या थायीमोक्जेम 75 डब्ल्यू. एस. के 5 मि.ली. या फेप्रोनिक् 5 एफ.एस. के 2 मि.ली. को 1-3 लीटर पानी में घोलकर प्रति किलो बीज मान से उपचारित कर लगायें।

● खड़ी फसल में दीमक नियंत्रण के लिये क्लोरोफायरीफॉस 20 ई.सी. 1 लीटर प्रति हेक्टर के मान से सिंचाई के पानी के साथ दें।

समस्या— मैं पालक लगाना चाहता हूँ, कृपया विधि तथा अच्छी जातियां बतायें।

— सुधाकर राव

समाधान— आप पालक लगाना चाहते हैं यह समय पालक लगाने के लिये उपयुक्त है आप निम्न उपाय करें—

● सभी प्रकार की भूमि में पैदा किया जा सकता है।

● जातियों में पूसा भारती, पूसा हरिता, अलग्रीन, पूसा ज्योति तथा जोबनेर ग्रीन।

● बीज की मात्रा 20-30 किलो बीज/हे. पर्याप्त होगी।

● उर्वरकों में 25 किलो यूरिया, 40 किलो सिंगल सुपर फास्फेट तथा 40 किलो म्यूरेंट ऑफ पोटाश/हे. की दर से डालें।

● बुआई का उचित समय सितम्बर से दिसम्बर।

● बुआई के 3-4 सप्ताह बाद से कटाई शुरू की जा सकती है। तथा 15-20 दिनों के अंतर से बराबर कटाई की जाये।

समस्या— मैं अजबाइन लगाना चाहता हूँ, कृषि तकनीकी से अवगत करायें।

— जसवंत गौड़

समाधान— आप मसाला फसल अजबाइन लगाना चाहते हैं खेती से अधिक लाभ कमाने के लिये कुछ नया करने की जरूरत है। आपके पड़ोस सुल्तानपुर में हल्दी की खेती बहुत की जाती रही है। आप निम्न तकनीक का पालन करें।

● भूमि जिसमें अजबाइन लगाना है में जल प्रबंध अच्छा हो।



● 3-4 किलो बीज/हे. की दर से लगता है बीज का उपचार 2 ग्राम थाईरम/ किलो बीज का करें।

● बीज में खाद या राख मिलाने से बीज में अच्छा अंतर आ जाता है और सघनता ठीक हो जाती है।

● बुआई का उचित समय अक्टूबर-नवम्बर है।

● उन्नत जातियों में लाभ सलेक्शन 1, लाभ सलेक्शन 2, आर.एच. 40 इत्यादि हैं। इसके अलावा एन.डी.30, एन.पी. 151, एन.पी. 66, एन.पी. 79, एन.पी. (जे.) 8 तथा एन.पी. (जे.) 15 प्रमुख हैं। जो कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में विकसित की गई हैं।

● गुजरात अजबाइन 1 भी अच्छी किस्म है। जिसे लगाया जा सकता है।

कृषक जगत

बागवानी सीरीज

साग-सब्जी उत्पादन
उन्नत तकनीक
रु. 95



कोड : 016

सब्जियों में
पौध संरक्षण
रु. 75



कोड : 017

मशरूम एक
लाभ अनेक
रु. 45



कोड : 019

मिर्च की
उन्नत खेती
रु. 55



कोड : 020

केला
उत्पादन
रु. 70



कोड : 025

गुलाब
बहुसंजी संशोधित
संस्करण
रु. 75



कोड : 027

पपीता

रु. 55



कोड : 031

अदरक

रु. 55



कोड : 032

फलों की
खेती

रु. 75



कोड : 040

सजाएं फूलों
से बगिया

रु. 65



कोड : 041

घर की
बगिया

रु. 95



कोड : 050

डाक द्वारा मंगवाने हेतु निम्नलिखित जानकारी के साथ हमारे पते पर ड्राफ्ट/ मनीऑर्डर के साथ ऑर्डर कीजिए. किताब कोड नं. पर ✓ निशान लगाएं

016 ☐ 017 ☐ 019 ☐ 020 ☐ 025 ☐ 027 ☐ 031 ☐ 032 ☐ 034 ☐ 040 ☐ 041 ☐ 050 ☐

नाम _____

ग्राम _____ पोस्ट _____ तह. _____

जिला _____ फोन/मोबा. _____

कुल राशि _____ ऑर्डर की गई प्रतियों की संख्या _____

संलग्न ड्राफ्ट नं. _____ मनी ऑर्डर रसीद क्र. _____ वी.पी. भेजें ☐

कृपया ड्राफ्ट या मनीऑर्डर कृषक जगत भोपाल के नाम

14, इंदिरा प्रेस काम्पलेक्स, एम.पी. नगर, भोपाल - 462011

फोन : 0755-4248100, 2554864, मो.: 9826255861, Email-info@krishakjagat.org

इंदौर : 331-332, आर्बिट माल, ए.बी. रोड, विजय नगर चौराहे के पास, इंदौर (म.प्र.) मो. : 9826021837

संस्थाओं द्वारा अधिक
संख्या में प्रतियां खरीदने
पर आकर्षक छूट.
अधिक जानकारी
के लिए सम्पर्क करें.

निवेदन

समस्या-समाधान स्तंभ में पाठकों से निवेदन है कि अपनी खेती-किसानी संबंधी समस्या कृषि विशेषज्ञों से निराकरण करने हेतु वाट्सएप पर भेजें. एक बार में केवल एक प्रमुख समस्या ही वाट्सएप पर लिखकर भेजें. वाट्सएप हेल्पलाइन नं. 6262166222.

समस्या-समाधान

कृषक जगत 14, इंदिरा प्रेस काम्पलेक्स,
महाराणा प्रताप नगर, भोपाल (म.प्र.)
फोन-0755-4248100, 2554864

स्वास्थ्य/शिक्षण

सावधान रहें, चोरी से आने वाली सर्दी से...

सर्दी आ गई है लेकिन तापमान में अभी कोई विशेष अंतर नहीं आया है। इसकी वजह मौसम की मौजूदा विसंगति भी है। लेकिन वजह चाहे जो हो, तापमान बढ़ते ही लोग सर्दी को लेकर लापरवाह हो जाते हैं। बस तभी यह धीरे-धीरे आती हुई सर्दी चुपके से कोल्ड और फ्लू के रूप में खतरनाक हमले शुरू कर देती है। सवाल है, इससे कैसे बचे रहें। तो चुपके से धावे बोलने वाली इस कोल्ड से बचने के बेहतर तरीके ये हैं—

- जितनी ज्यादा बार संभव हो अपने हाथ धोएं।

- अगर कोई कोल्ड या फ्लू से पीड़ित है तो उससे हाथ मिलाने, वायरसग्रस्त सतह जैसे दरवाजे के हैंडिल आदि छूने, फिर उन्हीं हाथों से अपनी आंखें मलने की वजह से कोल्ड होता है।

- रोजाना विटामिन-सी लें। इससे दस्तक देती गर्मी में भी आपकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और उपचार में भी तेजी आती है।
- ज्यादा तनाव से बचें क्योंकि तनाव आपके जिस्म में जो इन्फेक्शन से

लड़ने की क्षमता है उसमें बाधक बनता है।

- रोजाना तीस मिनट तक कसरत करने से भी कोल्ड और फ्लू से लड़ने में मदद मिलती है।

- कोल्ड और फ्लू में आमतौर पर भेद करना मुश्किल है। लेकिन फ्लू जरा



तेजी से आता है और कोल्ड की तुलना में जिस्म को ज्यादा तोड़ देता है। इसी से इसके फर्क को समझ लें।

- इसके अन्य लक्षणों में हैं— टांगों में दर्द, तेज तापमान का अहसास और पूरे

जिस्म में थकान। यह बहुत जल्दी दूसरे लोगों में भी फैलता है। कहने का मतलब यह कि यह बेहद संक्रामक है।

इससे बचने के तरीके हैं—

- खूब आराम करें।

- खूब तरल पेय पिएं।

- कोल्ड और फ्लू वायरस की वजह से होते हैं, इसलिए इनमें एंटीबायोटिक मदद नहीं करती।

- इस दौरान जरूरत से ज्यादा कसरत न करें।

- अमूमन कोल्ड या फ्लू होने से पहले गला खराब हो जाता है।

इस दौरान ● गर्म कढ़ी, चाय, कॉफी या गुनगुना नींबू पानी व शहद सिप करने से आराम मिलता है।

- हर आधा घंटे में नमक डालकर गुनगुने पानी से गरारे करने से दर्द और बेचैनी से राहत मिलती है।

- कोल्ड के जाने के बाद भी नाक आना और नाक बंद रहने का अहसास रहता है।

गेहूं चोकर में पोषक तत्वों का महत्व

गेहूं का चोकर प्रोटीन, मैग्नीशियम, मैंगनीज, नियासिन, फास्फोरस, जस्ता एवं विटामिन बी का समृद्ध स्रोत होता है। इसमें वसा की मात्रा कम होती है, जबकि यह कोलेस्ट्रॉल, शर्करा एवं सोडियम रहित होता है। इन्हीं कारणों से यह आंत के कार्य को सामान्य बनाए रखने, रक्त शर्करा एवं कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करने में मदद करता है। खान-पान की आदतों में बदलाव के कारण होने वाली कब्ज में राहत प्रदान करता है।

दैनिक आहार में अनुशंसित मात्रा
एक वयस्क व्यक्ति को गेहूं के चोकर की 20-30 ग्राम प्रति दिन सेवन करने के लिए अनुशंसित है। इसकी शुरुआत कम मात्रा से की जानी चाहिए। दिन में एक या दो चम्मच ही पर्याप्त है।

गेहूं चोकर के सेवन से स्वास्थ्य लाभ

मोटापे से निजात :

दैनिक आहार में कार्यात्मक फाइबर शामिल करना चाहिए। फाइबर से भरपूर गेहूं की चोकर को सुबह की स्मूदी तथा दही के साथ सेवन करने से शारीरिक वजन कम करने में मदद मिलती है।

बीमारियों को जोखिम कम करता है

उच्च फाइबर युक्त खाद्य पदार्थों के सेवन से कोलोन कैंसर, हृदय रोग एवं मधुमेह जैसे रोगों के जोखिम को कम करने में मददगार है।

आंत की बीमारियों में फायदेमंद
संवेदनशील आंत की बीमारी (दस्त/कब्ज के साथ पेट में दर्द) के प्रारम्भिक उपचार के लिए दैनिक आहार में उच्च फाइबर युक्त भोजन का सेवन करने से आराम मिलता है। भोजन में गेहूं की चोकर शामिल करने से फाइबर की मात्रा को बढ़ाया

जा सकता है। डायवर्टिकुलर रोग के लक्षण प्रतीत होने पर 45 ग्राम कच्चे असंसाधित गेहूं के चोकर का सेवन करने से आराम मिलता है।

कब्ज से राहत

महिलाओं में गर्भावस्था के दौरान गेहूं चोकर का सेवन कब्ज को कम करने के साथ मल निष्कासन की आवृत्ति को बढ़ाता है।



हृदय रोग प्रतिरोधी

गेहूं की चोकर में फाइटोकेमिकल एवं एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं। इसलिए, गेहूं का चोकर समावेशित अनाज वाले खाद्य पदार्थों का सेवन हृदय रोगों को रोकने में मदद करता है। गेहूं की चोकर घुलनशील लिपिड यौगिक एवं फाइटो केमिकल्स जैसे—फाइटेट्स, फाइटोस्टेरॉल, टोकोफेरॉल आदि का भी एक समृद्ध स्रोत है। इनमें से फाइटेट्स कोलोन कैंसर की रोकथाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

मधुमेह से राहत

फाइबर युक्त सभी प्रकार के फल मधुमेह से पीड़ित व्यक्तियों के लिए उपयुक्त नहीं होते हैं। लेकिन शरीर में इसकी आपूर्ति के लिए गेहूं का चोकर एक बेहतरीन माध्यम है।

आंखों के लिए फायदेमंद

गेहूं का चोकर मैग्नीशियम का भी अच्छा स्रोत है, जो मस्तिष्क, हृदय, आंख और नर्व को स्वस्थ रखने के साथ-साथ हड्डियों को

मजबूती प्रदान करता है।

एंटीऑक्सीडेंट के रूप में

गेहूं के चोकर में सेलेनियम प्राकृतिक रूप में अच्छी मात्रा में होता है, जो मानव शरीर में एंटीऑक्सीडेंट का कार्य करता है। हमारे शरीर को इसकी बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है। शरीर में सेलेनियम की संतुलित मात्रा हार्ट अटैक, कैंसर, एथेरोस्क्लेरोसिस एवं अस्थिमा जैसी बीमारियों को रोकने में मदद मिलती है। यह शरीर में उपस्थित टॉक्सिन को बाहर निकालने, प्रतिरोधक क्षमता एवं प्रजनन क्षमता को बढ़ाने में भी मददगार है।

घर की रसोई में गेहूं के चोकर का उपयोग

गेहूं चोकर का स्वाद मीठा होता है, लेकिन यह देखने में आकर्षक नहीं लगता है। इसको खाने में थोड़ा-थोड़ा उपयोग लाभदायक है, लेकिन थोड़ी सी अधिक मात्रा दस्तावर हो सकती है। मफिन्स, बिस्कुट, ब्रेड, पैनकेक, नूडल्स, स्नैक्स बन्स, वॉफले, कुकीज एवं केक आदि में गेहूं का चोकर मिलाकर पोषण गुणवत्ता एवं आहार रेशा की मात्रा बढ़ाने का बेहतर विकल्प है।

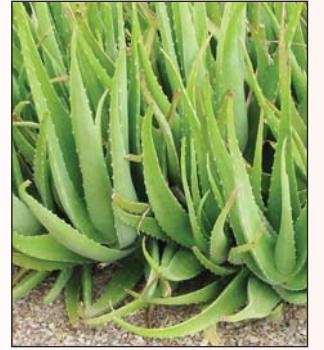
इसके महीन पाउडर की थोड़ी सी मात्रा के उपयोग से स्मूदीज को और अधिक पौष्टिक बनाया जा सकता है। शोध दर्शाते हैं कि तले हुए अनाज उत्पादों जैसे पूड़ी के आटे में 3 प्रतिशत गेहूं की चोकर को शामिल करने से पूड़ियाँ तलने में 20 प्रतिशत तेल की बचत होती है।

गेहूं चोकर के उपयोग में सावधानियाँ

गेहूं चोकर में फाइबर एवं ग्लूटेन की मात्रा अधिक होती है। इसलिए अधिक मात्रा में इसका सेवन पेट दर्द का कारण बन सकता है। जिन लोगों को ग्लूटेन से एलर्जी है, उन्हें चोकर के सेवन करने से बचना चाहिए।

एलोवेरा : गुणों का खजाना

भारत में ग्वारपाठा या घृतकुमारी हरी सब्जी के नाम से प्राचीनकाल से जाना जाने वाला कांटेदार पत्तियों वाला पौधा है, जिसमें रोग निवारण के गुण कूट-कूट कर भरे पड़े हैं। आयुर्वेद में इसे घृतकुमारी की उपाधि मिली हुई है तथा महाराजा का स्थान दिया गया है।



औषधि की दुनिया में इसे संजीवनी भी कहा जाता है। इसकी 200 जातियां होती हैं, परंतु प्रथम 5 ही मानव शरीर के लिए उपयोगी हैं।

इसकी बारना डेंसीस नाम की जाति प्रथम स्थान पर है। इसमें 18 धातु, 15 एमीनो एसिड और 12 विटामिन मौजूद होते हैं। इसकी तासीर गर्म होती है। यह खाने में बहुत पौष्टिक होता है। इसे त्वचा पर लगाना भी उतना ही लाभप्रद होता है। इसकी कांटेदार पत्तियों को छीलकर एवं काटकर रस निकाला जाता है। 3-4 चम्मच रस सुबह खाली पेट लेने से दिन-भर शरीर में शक्ति व चुस्ती-स्फूर्ति बनी रहती है।

जलने पर, अंग कहीं से कटने पर, अंदरूनी चोटों पर एलोवेरा अपने एंटी बैक्टेरिया और एंटी फंगल गुण के कारण घाव को जल्दी भरता है। यह रक्त में शर्करा के स्तर को बनाए रखता है। बवासीर, डायबिटीज, गर्भाशय के रोग, पेट की खराबी, जोड़ों का दर्द, त्वचा की खराबी, मुंहासे, रूखी त्वचा, धूप से झुलसी त्वचा, झुर्रियों, चेहरे के दाग-धब्बों, आंखों के काले घेरों, फटी एड़ियों के लिए यह लाभप्रद है। इसका गूदा या जैल निकालकर बालों की जड़ों में लगाना चाहिए। बाल काले, घने-लंबे एवं मजबूत होंगे। यह मच्छर से भी त्वचा की सुरक्षा करता है। आजकल सौन्दर्य निखार के लिए हर्बल कॉस्मेटिक उत्पाद के रूप में बाजार में एलोवेरा जैल, बॉडी लोशन, हेयर जैल, स्किन जैल, शैंपू, साबुन, फेशियल फोम, और ब्यूटी क्रीम में हेयर स्पा में ब्यूटी पार्लरों में धड़ल्ले से प्रयोग हो रहा है। कम से कम जगह में, छोटे-छोटे गमले में एलोवेरा आसानी से उगाया जा सकता है। एलोवेरा जैल या ज्यूस मेहंदी में मिलाकर बालों में लगाने से बाल चमकदार व स्वस्थ होंगे। एलोवेरा के कण-कण में सुंदर एवं स्वस्थ रहने के कई-कई राज छुपे पड़े हैं। यह संपूर्ण शरीर का कायाकल्प करता है।

पाक्षिक पंचांग

6 से 19 अक्टूबर 2025

विक्रम संवत् 2082

आश्विन शुक्ल 14 से कार्तिक कृष्ण 13 तक

दि.	माह	वार	तिथि/त्यौहार
6	अक्टूबर	सोम	आश्विन शुक्ल 14 शरद पूर्णिमा, पंचक
7	अक्टूबर	मंगल	----- 15 स्ना.दा. पूर्णिमा पंचक 3.18 रात तक
8	अक्टूबर	बुध	कार्तिक कृष्ण 1/2
9	अक्टूबर	गुरु	----- 3
10	अक्टूबर	शुक्र	----- 4 करवा चौथ व्रत
11	अक्टूबर	शनि	----- 5
12	अक्टूबर	रवि	----- 6 स्कंध षष्ठी व्रत
13	अक्टूबर	सोम	----- 7
14	अक्टूबर	मंगल	----- 8
15	अक्टूबर	बुध	----- 9
16	अक्टूबर	गुरु	----- 10
17	अक्टूबर	शुक्र	----- 11 रंभा एकादशी
18	अक्टूबर	शनि	----- 12 प्रदोष व्रत, धनतेरस
19	अक्टूबर	रवि	----- 13 शिव चतुर्थी व्रत

प्राकृतिक खेती से जीवन-मिट्टी होगी स्वस्थ : श्री सोने



रायसेन (कृषक जगत)। रासायनिक उर्वरक के अंधाधुंध उपयोग से मनुष्य में गंभीर बीमारी के साथ मिट्टी की सेहत भी कम हो गई है। मनुष्य स्वास्थ्य एवं जलवायु को प्रदूषण से बचाने के लिए प्राकृतिक खेती ही एक ऐसा उपाय है जिससे वर्तमान समय में मनुष्य व खेती की भूमि को स्वस्थ बनाए जा सकता है। यह बात जिले में पांच दिवसीय कृषि सखी प्रशिक्षण शुभारंभ अवसर पर प्राकृतिक खेती के अधिकारी सहायक संचालक कृषि श्री सुनील कुमार सोने ने संबोधित कर कही।

कृषि विज्ञान केंद्र रायसेन में उप संचालक श्री के. पी. भगत के मार्गदर्शन में आयोजित प्रशिक्षण में किसानों को प्राकृतिक खेती करने के लिए कृषि सखी प्रशिक्षण लेकर प्राकृतिक खेती सूत्रों का विस्तार करेगी। प्रशिक्षण में जीवामृत, घनजीवामृत, बीजामृत, अग्निअस्त्र, आच्छादन, नीमास्त्र, ब्रह्मास्त्र

निर्माण की जानकारी के साथ इनका कृषि में उपयोग समझाया जाएगा।

प्रशिक्षण में कृषि में सूक्ष्म जलवायु प्रबंधन तकनीक, फसलों में रस सूचक कीट नियंत्रण जिले की फसलों को प्राकृतिक खेती से करने के तरीके प्रमुख हैं। प्रशिक्षण शुभारंभ अवसर पर डॉ. एम. डी. व्यास पूर्व प्रधान वैज्ञानिक कृषि महाविद्यालय सीहोर, कार्यक्रम समन्वयक कृषि विज्ञान केंद्र डॉ. स्वप्निल दुबे, केंद्र के वैज्ञानिक डॉ. मुकुल कुमार, डॉ. प्रदीप कुमार द्विवेदी, श्री आलोक कुमार सूर्यवंशी सहित सभी विकासखंडों की कृषि सखी उपस्थित थीं। जिले के सभी ब्लॉकों में 25 क्लस्टर का निर्माण कर 50 कृषि सखियों को चयनित कर प्रशिक्षित किया जा रहा है। यह प्रशिक्षण आगामी समय में पंजीकृत कृषकों को विकासखंड स्तर पर भी दिए जाएंगे।

एनएफएल ने बताए संतुलित उर्वरक उपयोग के तरीके

खरगोन (कृषक जगत)। नेशनल फर्टिलाइजर लि. (एनएफएल) ने पी.एम. के. एस.के. बमनाला में किसान संगोष्ठी आयोजित कर उर्वरक उपयोग के तरीके बताए। एनएफएल के क्षेत्रीय कार्यालय, इंदौर के अंतर्गत पी.एम.-प्रणाम किसान प्रशिक्षण कार्यक्रम में कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक डॉ. वाय. के. जैन, क्षेत्रीय कार्यालय इंदौर प्रभारी श्री सुमित गर्ग भी मौजूद थे। वैज्ञानिक डॉ. जैन ने एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन, रासायनिक उर्वरक के साथ-साथ जैविक उर्वरक और कार्बनिक खाद के उपयोग के तरीके, नैनो डीएपी, नैनो यूरिया, पीडीएम, कंपोस्ट खाद, एफओएम, सी वीड एवं बायो फर्टिलाइजर्स के उपयोग करने की जानकारी दी। एनएफएल के श्री गर्ग ने भारतीय जन उर्वरक परियोजना, उर्वरक प्लांट, विभिन्न उत्पादों, POS सेल, और उर्वरक के संतुलित उपयोग के बारे में बताया। कार्यक्रम में जिला प्रभारी खरगोन श्री अजय चौहान सहित फैकल्टी एवं किसान उपस्थित थे।



जीएसटी सुधार का एनएफएल ने किया स्वागत

नोएडा (कृषक जगत)। नेशनल फर्टिलाइजर लि. (एनएफएल) ने भारत सरकार द्वारा जीएसटी की दरों में किए गए सुधारों की सराहना की है। कच्चे माल की लागत में कमी से घरेलू उर्वरक उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा वहीं किसानों को सस्ती दर पर उपलब्ध हो सकेगा।

एनएफएल ने जीएसटी सुधारों का स्वागत करते हुए इसे उर्वरक उद्योग एवं किसानों दोनों के लिए फायदेमंद बताया साथ ही उर्वरक क्षेत्र को अत्यधिक बढ़ावा मिलने की बात कही।

नाइट्रोजन और एनपीके उर्वरक निर्माण के लिए आवश्यक इनपुट जैसे अमोनियम, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रेट एसिड पर जीएसटी दर को 18 से घटकर 5 फीसदी, सूक्ष्म पोषक तत्वों पर 12 से घटकर 5 फीसदी किया गया है। जीएसटी कटौती से घरेलू उर्वरक उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। उर्वरक कंपनियों को कच्चे माल की लागत में काफी बचत होगी जिससे किसानों को सस्ती दरों पर उर्वरक उपलब्ध हो सकेगा। सूक्ष्म पोषक तत्वों पर जीएसटी कटौती पीएम प्रणाम योजना कार्यक्रम के अंतर्गत की गई है।

कृषि सखी प्राकृतिक खेती को देगी बढ़ावा



धार (कृषक जगत)। कृषि विज्ञान केंद्र मनावर में प्राकृतिक खेती पर पांच दिवसीय कृषि सखी प्रशिक्षण के समापन अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री महिला एवं बाल विकास श्रीमती सावित्री ठाकुर उपस्थित रहीं। उन्होंने संबोधित कर कृषि सखियों को क्षेत्र में प्राकृतिक खेती बढ़ाने के लिए सतत् प्रयास करने की बात कही। प्राकृतिक खेती के सभी विकल्पों का प्रचार-प्रसार करके कृषकों का रुझान इस दिशा में किया जाय। श्रीमती ठाकुर ने रासायनिक खादों के अत्यधिक प्रयोग से होने वाले नुकसान एवं प्राकृतिक खेती के फायदे भी बताए। सबमिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन एजेंसी (आत्मा) द्वारा आयोजित प्रशिक्षण में कृषि

सखी को प्राकृतिक खेती के विकल्प जीवामृत, घनजीवामृत, बीजामृत, अग्निअस्त्र, आच्छादन, नीमास्त्र, ब्रह्मास्त्र के निर्माण एवं उपयोग की जानकारी दी गई।

प्रशिक्षण अवसर पर जिला पंचायत सदस्य श्री चंचल पाटीदार, कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक डॉ. ए. एल. बसेड़िया, परियोजना संचालक आत्मा सह उपसंचालक कृषि श्री ज्ञान सिंह मोहनिया, उप परियोजना संचालक आत्मा श्री के. एस. झाणिया, कृषि वैज्ञानिक डॉ. नरेश गुप्ता, डॉ. डी. के. सूर्यवंशी एवं श्री डी. आर. चौहान, श्री जितेंद्र सोलंकी उपस्थित रहे। कार्यक्रम पश्चात केंद्रीय मंत्री ने कृषि सखियों को प्रमाण पत्रों का वितरण किया।



कृषक जगत

राष्ट्रीय कृषि अखबार



जगत

भोपाल-जयपुर-रायपुर



वर्ष में कई आकर्षक एवं संग्रहणीय विशेषांक

- खरीफ विशेषांक
- पौध संरक्षण विशेषांक
- रबी विशेषांक
- बीज विशेषांक
- बागवानी विशेषांक

25 लाख पाठक

कृषक जगत की सदस्यता राशि	⇒ वार्षिक रु. 600/- ⇒ दो वर्ष रु. 1000/- ⇒ तीन वर्ष रु. 1500/-	
---------------------------------	--	--

डाक से नियमित रूप से 'कृषक जगत' - प्रति सप्ताह □ भोपाल □ जयपुर □ रायपुर संस्करण निम्न पते पर एक वर्ष/दो वर्ष / तीन वर्ष भेजे। (अपनी आवश्यकता के अनुरूप निशान लगायें)।

नाम

ग्रामपो.

डाक वितरण हेतु अपने क्षेत्रीय पोस्टमैन का मो. नं. अवश्य दें :

वि.ख.तह.

जिलापिन [] [] [] [] राज्य

शिक्षा भूमि उम्र

ट्रेक्टर/मॉडल फोन/मो.

ई-मेल

मेरा सदस्यता शुल्क रुपये नगद/डिमांड ड्राफ्ट/UPI/Bank/मनीऑर्डर/क्र. 'कृषक जगत' भोपाल के नाम संलग्न है।

कृषक जगत में सदस्यता लेने के माध्यम

कृषक जगत ऑनलाइन पेमेंट लिंक

Online Payment- SBI-A/C No. 53007193070, IFSC : SBIN 0005793, Google Pay/Phone Pe/PAYTM/UPI : Mobile 9826255861

http://www.krishakjagat.org/krishak-jagat-subscription/index.php कृषक जगत हेल्पलाइन नम्बर 6262166222

पेमेंट के बाद : 1. पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजें इस फोन नम्बर पर 9826255861
2. पूरा नाम, पता पिन कोड के साथ भेजें।

अधिक जानकारी के लिए सम्पर्क करें

प्रसार प्रबंधक कृषक जगत

भोपाल : 14, इंदिरा प्रेस काम्पलेक्स, एम.पी. नगर, भोपाल-462011 फोन: 0755-4248100, मो. : 9926653355, 9826255861, E-mail-info@krishakjagat.org

जयपुर : एच-64, मीरा मार्ग, बनी पार्क, जयपुर (राज.), मो. : 9829254092, 7387422952

रायपुर : एलआईजी-5, सेक्टर-2, शंकर नगर, रायपुर (छ.ग.), मो.: 9826255862

इंदौर : 331-332, आर्विट माल, ए.बी. रोड, विजय नगर चौराहे के पास इंदौर, मो. : 9826021837, 9826024864

नई दिल्ली : 403,आईएनएस बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली, मो. : 7387422952

सदस्यता शुल्क भुगतान के लिए QR कोड स्कैन करें





कटंगी कृषि मेले में नरसिंहपुर की गाडरवारा तुअर दाल बनाने की जीवंत तकनीक प्रदर्शनी में आकर्षण का केन्द्र रही, प्रदर्शनी का अवलोकन करते संयुक्त संचालक कृषि जबलपुर संभाग श्री के. एस. नेताम, उपसंचालक कृषि छिन्दवाड़ा श्री जितेन्द्र कुमार सिंह एवं नरसिंहपुर उप संचालक कृषि श्री मोरीस नाथ।

एसएडीओ संघ ने सचिव को सौंपा ज्ञापन



भोपाल (कृषक जगत)। वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी संघ के प्रतिनिधिमंडल ने कृषि सचिव को वल्लभ भवन पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। इस दौरान संघ के अध्यक्ष श्री दिलावर सिंह कौरव, पूर्व ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष श्री मनोहर लाल गिरी, वर्तमान प्रांत अध्यक्ष श्री मोहन डामोर, श्री चेतन पाटीदार (मन्दसौर), श्री

सत्यनारायण जाट, श्री संतोष शर्मा, श्री राहुल जायसवाल (देवास) एवं श्री संतोष पाटीदार (धार) उपस्थित थे। सचिव से वार्ता के दौरान संगठन से संबंधित समस्याओं, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी पद को राजपत्रित किए जाने, वेतन विसंगति दूर करने तथा समयमान जैसी महत्वपूर्ण मांगों पर विस्तार से चर्चा की।

कविता को ड्रोन दीदी के नाम से मिली नई पहचान

मुरैना (कृषक जगत)। ड्रोन तकनीक ने कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाया है। खेती को आधुनिक और लाभकारी बनाने के लिए केंद्र



सरकार द्वारा 'नमो ड्रोन दीदी योजना' प्रारंभ की गई है, जिसके माध्यम से महिलाओं को ड्रोन संचालन का प्रशिक्षण देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। मुरैना जिले के कैलारस विकासखंड के ग्राम जैरैना-मानगढ़ की निवासी श्रीमती कविता कुशवाह आज पूरे क्षेत्र में 'ड्रोन दीदी' के नाम से जानी जाती हैं। तीन वर्ष पूर्व मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत गांव में स्वयं सहायता समूह का गठन हुआ, जिसमें श्रीमती कविता को अध्यक्ष चुना गया। शासन द्वारा सीसीएल (Community Investment Fund) के तहत 1 लाख की सहायता राशि प्राप्त हुई, जिससे उन्होंने

सिलाई की दुकान प्रारंभ की। इसके बाद प्रधानमंत्री की पहल पर शुरू हुई नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत उन्होंने ड्रोन चलाने का प्रशिक्षण प्राप्त किया। आज श्रीमती कविता खेतों में जाकर ड्रोन के माध्यम से कीटनाशकों एवं रासायनिक दवाओं का छिड़काव करती हैं। उनका कहना है कि इससे न केवल किसानों को लाभ होता है, बल्कि पानी की भी बचत होती है लागत घटती है और छिड़काव का कार्य तेजी से पूरा होता है। ड्रोन से मात्र 7 मिनट में 1 हेक्टेयर क्षेत्र में छिड़काव संभव है। किसान किसानोदय एप के माध्यम से उनसे संपर्क करते हैं, जिसके बाद वे खेतों में जाकर सेवा प्रदान करती हैं।

उर्वरक विक्रय लाइसेंस निलंबित

जबलपुर (कृषक जगत)। किसानों को निर्धारित दर से अधिक कीमत पर उर्वरक विक्रय करने का दोषी पाये जाने पर उप संचालक कृषि डॉ. एस. के. निगम ने बरगी स्थित मेसर्स पिपलेश्वर महादेव का उर्वरक विक्रय लाइसेंस निलंबित कर दिया है। जानकारी के अनुसार मेसर्स पिपलेश्वर महादेव का उर्वरक लाइसेंस निलंबित करने की यह कार्यवाही इस प्रतिष्ठान से अधिक दर पर उर्वरक का विक्रय करने का वीडियो वायरल होने पर निरीक्षण के बाद की गई है।

3 डीलरों को नोटिस दिए

भिंड (कृषक जगत)। भिंड में तीन निजी उर्वरक विक्रेताओं को अनियमितताओं के चलते नोटिस जारी किया गया है। उप संचालक भिंड श्री के. के. पाण्डेय ने मेसर्स पंडित रामदयाल एंड संस पुरानी गल्ला मंडी भिंड, मेसर्स कुसुमकांत जैन पुरानी गल्ला मंडी भिंड, मेसर्स निमित फर्टिलाइजर पुरानी गल्ला मंडी भिंड को कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर दिया है।

श्री पाण्डेय ने नोटिस जारी कर कहा है कि कलेक्टर भिंड के निर्देशानुसार जिले में किसानों को सुगमता से उर्वरक उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आपको लगातार व्यक्तिगत रूप से पत्राचार द्वारा निर्देशित किया गया है कि रैक पॉइंट से प्राप्त स्कंध सीधे फुटकर विक्रेताओं को उप

संचालक कृषि को सूचित किये बिना ही प्रदाय किया जा रहा है। जिससे जिले को प्राप्त उर्वरक स्कंध की जानकारी न होने से उर्वरक वितरण में कठिनाई उत्पन्न हो रही है तथा जिले में कानून व्यवस्था जैसी स्थिति निर्मित हो रही है। इससे प्रतीत हो रहा रहा है कि आपके द्वारा उर्वरक वितरण व्यवस्था में दिये गये निर्देशों की लगातार अवहेलना

की जा रही है। जो कि उर्वरक गुण नियंत्रण 1985 में निहित प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है।

इस संबंध में आप अपना स्पष्टीकरण तत्काल उर्वरक निरीक्षक भिंड के माध्यम से प्रस्तुत करें, अन्यथा आपको देय अनुज्ञप्ति को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए उर्वरक आईडी को निरस्त करने की कार्यवाही की जावेगी।

कृषक जगत की सदस्यता हेतु संपर्क करें

शैलेन्द्र फरक्या, बलराम एंड ब्रदर्स, पिपलिया मंडी,
जिला- मन्दसौर, मो. : 9893189345
सतीशचन्द्र शर्मा, मे. शर्मा एग्रो एजेन्सी, पनवाड़ी,
जिला-शाजापुर, मो. : 9893296531

पटवारी एग्रो एजेन्सी

:: वितरक ::

- ◆ कलश सीड्स लि. ◆ बायोस्टेट इंडिया लि. ◆ बाँयर कॉप साइंस ◆ धानुका एग्रीटेक लि.
- ◆ एफ.एम.सी. इंडिया प्रा.लि. ◆ घरड़ा केमिकल्स लि. ◆ अतुल एग्रीटेक लि.
- ◆ रामा फॉस्फेट्स लि. ◆ जी.एन.एफ.सी. ◆ इंसेक्टिसाइड्स इंडिया लि. ◆ बीएएसएफ
- ◆ ड्यूपोंट इंडिया लि. ◆ क्रिस्टल क्राप साइंस ◆ डाउग्लो साइंसेस ◆ एग्री सर्व इंडिया
- ◆ मंशा इंडिया लि. ◆ स्वाल कार्पोरेशन लि. ◆ मेघमनी ऑर्गेनिक्स ◆ अदामा इंडिया लि.

17, विशाल टॉवर, इंदिरा काम्पलेक्स, नवलखा चौराहा, इन्दौर (म.प्र.)
फोन : 2403694, 2400412, मो. : 9425077083



कई प्रकार की फसलों
के लिए एकमात्र
स्वचलित गियर ड्राईव

वरदान
मल्टीक्रॉप
पावर रीपर

वरदान एग्री सॉल्यूशन्स प्रा.लि.

63, पोलोग्राउण्ड, इन्दौर-452015 (म.प्र.) फोन: 0731-4970600, 6264916090.

छोटा विज्ञापन बड़ा लाभ

व्यक्तिगत क्लासीफाईड

विज्ञापन के लिए निर्धारित कैटेगरीज-

- बेचना/खरीदना- ट्रैक्टर, ट्राली, शेथर, खेत, मकान, मोटरसाइकल, पशु, मोटर, जनरेटर आदि ■ बीज ■ औषधीय फसल
- विज्ञापन दर - मात्र रु. 600/- प्रति संस्करण लगातार 4 सप्ताह तक ■ अधिकतम 25 शब्द
- अतिरिक्त शब्द- 2 रु. प्रति शब्द, अधिकतम 40 शब्दों तक

डिस्प्ले क्लासीफाईड

विज्ञापन दर : रु. 800/- प्रति अंक, प्रति संस्करण जीएसटी 5% अतिरिक्त
साइज : फिक्स साइज- 8 x 5 = 40 वर्ग से.मी.
कैटेगरीज- बीज, कीटनाशक, जैविक खाद, ट्रैक्टर, तीर्थ यात्राएं, आवश्यकता, ऑटोमोबाइल पार्ट्स, कृषि सेवा केन्द्र, शिक्षण संस्थाएं, प्रशिक्षण, बारदाने, कोल्ड स्टोरेज, गोदाम, होस्टल, वित्तीय संस्थाएं, चिकित्सक, एग्री क्लीनिक आदि।

कृषक जगत

की सदस्यता एवं विज्ञापन के लिए हेल्पलाइन नं.

62 62 166 222

www.krishakjagat.org @krishakjagatindia
@krishakjagat @krishak_jagat

कैरा टेक्नोप्लास्ट प्रा.लि.,
खरगोन

आपकी समृद्धि
हमारी प्राथमिकता

हमारे यहां पर ड्रिप में प्लैट और राउण्ड एचडीपीई व स्प्रिंकलर पाईप, एचडीपीई क्वाइल, लपेटा पाईप एवं रेन पाईप वर्जिन एवं उच्च क्वालिटी में बनाये जाते हैं। सम्पर्क - निरंजन नगर, कसरावद रोड, खरगोन,
मो. : 7880017028, 7880017021

TerraGlebe Farmers Producer Company Limited NIMADFRESH

यूरोप में मिर्च निर्यात (एक्सपोर्ट) करने वाला मध्यप्रदेश का पहला किसान उत्पादक संगठन बना 'टेरालेब' अब उसी की तर्ज पर नाबाई से गठित FPO निमाडफ्रेश FPO रसायन मुक्त मसाले का बना मैनुफैक्चर ODOP - मिर्च-खरगोन

निमाडफ्रेश FPO (JV) हरिओम भुरे 8964087240 टेरालेब FPO बालकृष्ण पाटीदार 9575524408

भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त नर्सरी

ISO 9001 : 2015 सर्टिफाईड

किसान हाईटेक ग्रीनहाउस नर्सरी

द्वारा पपीता, मिर्च, टमाटर, बैंगन, तरबूज, करेला, पल्लंगोभी, फूलगोभी आदि सब्जियों के पौधे टेबल स्टेण्ड के ऊपर रखकर तैयार किए जाते हैं सम्पर्क : 9407361901, 9407361902, 9407361903 सहयोगी प्रतिष्ठान : बागवानी बाजार नर्सरी जहां पर फलदार, सजावटी व फारेस्ट्री पौधों की विस्तृत श्रृंखला उपलब्ध है। संपर्क : मो. : 9407853117, 9407853118, 9407853119, नर्सरी स्थल : ग्राम-सिरलाय, तह.- बड़वाह 451115, जिला-खरगोन (म.प्र.)

मध्यभारत की सबसे बड़ी नर्सरी

तिरुपति ग्रीन हाउस नर्सरी

देश का सबसे बड़ा पौध भंडार औषधीय, फलदार, सजावटी फूलों के पौधे, इनडोर, टिश्यूकल्चर, क्रोपर, बोन्साई, सक्यूलेन्स, केक्टस, हैमिंग प्लांट, वर्टीकल प्लांट, लकी बैबू रेंज, फॉरेस्ट्री प्लांट एवं सब्जियों के पौधों की विस्तृत श्रृंखला में

: आपका स्वागत है : सिरलाय (बड़वाह) मध्यप्रदेश www.tirupatinursery.com email : tirupatinursery@gmail.com मो. : 9479457720/99/63/ 86/96/16/17/13/31/51

महिंद्रा ने सितम्बर में 65 हजार ट्रैक्टर बेचे



मुंबई (कृषक जगत)। महिंद्रा समूह के हिस्से, महिंद्रा एंड महिंद्रा लि. के फार्म इक्विपमेंट बिजनेस (एफईबी) ने सितंबर 2025 के लिए अपने ट्रैक्टर बिक्री आंकड़ों की घोषणा की। सितंबर 2025 में घरेलू बिक्री 64,946 इकाई थी, जबकि सितंबर 2024 में 43,201 इकाई थी, जो ग्राहकों को जीएसटी में कमी के लाभ और पिछले साल की त्योहारी अवधि की तुलना में इस साल नवरात्रि को सितंबर में आगे बढ़ाने के कारण 50 प्रतिशत साल-दर-साल वृद्धि को दर्शाती है। सितंबर 2025 के दौरान कुल ट्रैक्टर बिक्री (घरेलू + निर्यात) 66,111 इकाई रही, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में 44,256 इकाई थी। इस महीने निर्यात 1,165 इकाई रहा। प्रदर्शन पर टिप्पणी करते हुए, महिंद्रा एंड महिंद्रा लि. के कृषि उपकरण व्यवसाय के अध्यक्ष, श्री विजय नाकरा ने कहा, 'हमने सितंबर के दौरान घरेलू बाजार में 64,946 ट्रैक्टर बेचे हैं, जो पिछले साल की तुलना में 50 प्रतिशत अधिक है। प्रधानमंत्री द्वारा जीएसटी दरों में कटौती के फैसले से, पिछले साल अक्टूबर की तुलना में इस साल सितंबर महीने में नवरात्रि में बिक्री में वृद्धि हुई। खरीफ की सकारात्मक संभावनाओं, इस मौसम में बुआई के रकबे में वृद्धि और सामान्य से बेहतर मानसून जैसे कारकों ने इसे और मजबूत किया है।'



सितंबर के दौरान घरेलू बाजार में 64,946 ट्रैक्टर बेचे हैं, जो पिछले साल की तुलना में 50 प्रतिशत अधिक है। प्रधानमंत्री द्वारा जीएसटी दरों में कटौती के फैसले से, पिछले साल अक्टूबर की तुलना में इस साल सितंबर महीने में नवरात्रि में बिक्री में वृद्धि हुई। खरीफ की सकारात्मक संभावनाओं, इस मौसम में बुआई के रकबे में वृद्धि और सामान्य से बेहतर मानसून जैसे कारकों ने इसे और मजबूत किया है।'

दीर्घकालिक उत्पादकता के लिए उन्नत तकनीकों को अपनाएं : डॉ. राव

भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, क्षेत्रीय केंद्र इंदौर ने 74वाँ स्थापना दिवस मनाया



इंदौर (कृषक जगत)। भा.कृ.अ.प.- भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (आईएआरआई), इंदौर ने गत दिनों अपना 74वाँ स्थापना दिवस मनाया। मुख्य अतिथि डॉ. सीएच. श्रीनिवास राव, निदेशक एवं कुलपति, भा.कृ.अ.प.- भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली थे। विशिष्ट अतिथि में डॉ. के.एच. सिंह, निदेशक, आईसीएआर - एनएसआरआई, इंदौर तथा डॉ. भरत सिंह, डीन, कृषि महाविद्यालय, आरवीएसकेवीवी, इंदौर शामिल हुए। समारोह में 100 से अधिक किसानों सहित वैज्ञानिकों, हितधारकों और पूर्व कर्मचारियों की उल्लेखनीय भागीदारी रही।

डॉ. राव ने किसानों, वैज्ञानिकों और उद्योगों के बीच सुदृढ़ सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया, ताकि प्रौद्योगिकी का प्रभावी हस्तांतरण और कृषि में स्थिरता सुनिश्चित हो सके। अपने उद्बोधन में उन्होंने मृदा एवं जल संरक्षण को टिकाऊ कृषि की आधारशिला बताते हुए वैज्ञानिकों और किसानों से दीर्घकालिक उत्पादकता हेतु उन्नत तकनीकों को अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने बताया कि मध्य क्षेत्र (Central Zone) में लगभग 100% मालवी/कठिया गेहूं आईएआरआई, क्षेत्रीय केंद्र, इंदौर द्वारा विकसित किस्मों जैसे- गेहूं 8777, मंगल, पोषण, अनुपम, तेजस से आच्छादित है, जो संस्थान और

किसानों के लिए गर्व का विषय है। इसी प्रकार, देशभर में बोए जाने वाले 55-60 प्रतिशत चपाती गेहूं की किस्में भी आईएआरआई द्वारा विकसित की गई हैं, जो खाद्य सुरक्षा में संस्थान की अग्रणी भूमिका को दर्शाती हैं। निदेशक ने विशेष रूप से इंदौर केंद्र से विकसित गेहूं की उन किस्मों की सराहना की जो भूरा, काला रतुआ रोग से अवरोधी हैं। इन किस्मों से फफूंदनाशी दवाओं का छिड़काव कम करना संभव हो पाता है, जिससे किसानों का लागत में बचाव होता है। उन्होंने यह भी बताया कि इंदौर केंद्र से लोकप्रिय बनाए गए शरबती गेहूं की किस्में अपनी उत्कृष्ट रोटी गुणवत्ता के लिए देशभर में प्रसिद्ध हैं। इनमें सुजाता, हर्षिता, अमृता, पूसा उजाला, पूसा हर्षा और पूसा गेहूं शरबती प्रमुख हैं। डॉ. राव ने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, क्षेत्रीय केंद्र, इंदौर द्वारा विकसित गेहूं किस्मों पर आधारित प्रकाशन का विमोचन भी किया।

डॉ. के. एच. सिंह ने गेहूं-सोयाबीन प्रणाली पर दिए व्याख्यान में बताया कि यह पद्धति किसानों और उद्योगों दोनों के लिए लाभकारी है। वहीं, डॉ. भरत सिंह ने कहा कि मिट्टी की गुणवत्ता और अखंडता बनाए रखना अति आवश्यक है। इसके पूर्व अपने स्वागत भाषण में अध्यक्ष डॉ. जे.बी. सिंह, क्षेत्रीय केंद्र, इंदौर ने केंद्र की उपलब्धियां बताईं।

इफको का नया जैव उत्तेजक 'धराअमृत'

किसानों को जलवायु चुनौतियों से लड़ने में करेगा मदद

इफको ने कृषि क्षेत्र में सतत विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अपना नवीनतम जैव उत्तेजक (बायो-स्टिमूलेंट) 'धराअमृत' लॉन्च किया है। यह उत्पाद विशेष रूप से किसानों की फसलों की पैदावार बढ़ाने और पौधों के स्वास्थ्य को मजबूत बनाने के लिए वैज्ञानिक रूप से विकसित किया गया है। 'धराअमृत' में अमीनो एसिड, एल्विनिक एसिड, कार्बन और जरूरी सूक्ष्म खनिज शामिल हैं, जो उन्नत कॉलॉइडल प्रोसेसिंग तकनीक से तैयार किए गए हैं। यह जैव उत्तेजक पौधों के चयापचय को नियंत्रित करता है, कोशिकाओं की संरचना मजबूत करता है और पौधों की पोषक तत्वों को अवशोषित करने की क्षमता बढ़ाता है।



इसे 1 लीटर पानी में 10 मिलीलीटर मिलाकर प्रयोग किया जाता है। ड्रोन स्प्रे के लिए 500 मिलीलीटर 'धराअमृत' को 9.5 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव किया जाता है। यह नैनो यूरिया प्लस, नैनो डीएपी, नैनो ज़िंक, नैनो कॉपर, फोलियर न्यूट्रिएंट्स, कीटनाशक और फंगीसाइड्स के साथ पूरी तरह से संगत है।

लॉन्च इवेंट और प्रमुख उपस्थित लोग 'धराअमृत' के लॉन्च कार्यक्रम में गुजरात सरकार के कृषि मंत्री श्री राघवजी भाई पटेल मुख्य अतिथि थे। इसके अलावा, सांसद श्री पुरुषोत्तम रूपाला, इफको के अध्यक्ष श्री दिलीप सांघानी, प्रबंध निदेशक श्री के. जे. पटेल, इफको-नैनोवेंशन्स के एमडी डॉ. ए. लक्ष्मणन

समेत कई वरिष्ठ अधिकारी और राज्य के किसान भी इस मौके पर उपस्थित थे। इस कार्यक्रम ने कृषि क्षेत्र में नवीनतम तकनीकों को अपनाने और किसानों को सशक्त बनाने के लिए इफको की प्रतिबद्धता को दोहराया।

धराअमृत के फायदे

- फसलों की प्रकाश संश्लेषण क्षमता में वृद्धि
- पौधों के स्वास्थ्य और रोग प्रतिरोधक क्षमता में सुधार
- फसल की पैदावार और गुणवत्ता दोनों में बढ़ोतरी
- सभी प्रकार के फोलियर पोषक तत्वों के साथ पूरी तरह संगत
- विभिन्न फसल प्रणालियों में आसानी से उपयोग किया जा सकता है

ग्रोमैक्स ने 8 नए ट्रैक्टर लॉन्च किए



मुंबई (कृषक जगत)। महिंद्रा एंड महिंद्रा लि. और गुजरात सरकार के बीच एक संयुक्त उद्यम ग्रोमैक्स एग्री इक्विपमेंट लि. ने 4WD और 2WD श्रेणियों में ट्रैक स्टार सीरीज के 8 नए ट्रैक्टर लॉन्च किए हैं, जिसमें 50 एचपी से कम सेगमेंट में भारत की पहली फैक्ट्री-फिटिड केबिन श्रृंखला शामिल है।

ग्रोमैक्स के नए ट्रैक्टर बेहतरीन प्रदर्शन और संचालन में आसान हैं, जो खेती की सभी जरूरतों को पूरा करते हैं। ये नए ट्रैक्टर बाग की खेती, सुपारी की खेती, अंतर-खेती, पडलिंग और ढुलाई जैसे कार्यों को पूरा करेंगे। अपनी ट्रैक स्टार कवच श्रृंखला के अंतर्गत, ग्रोमैक्स ने 50 एचपी से कम क्षमता वाले ट्रैक्टरों में भारत की पहली फैक्ट्री-फिटिड केबिन श्रृंखला पेश की है, जिसे किसानों को सुरक्षित, आरामदायक और मौसम-रोधी कार्यस्थल प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।



लॉन्च पर टिप्पणी करते हुए, महिंद्रा एंड महिंद्रा लि. के कृषि उपकरण व्यवसाय के अध्यक्ष श्री विजय नाकरा ने कहा, 'ग्रोमैक्स में हमें एक ही दिन में

आठ नए ट्रैक्टरों का अनावरण करने पर गर्व है। त्योहारी सीजन के साथ, नए ट्रैक्टर अक्टूबर 2025 से ग्रोमैक्स डीलरशिप पर उपलब्ध होंगे। त्योहारी सीजन के दौरान, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में ग्रोमैक्स डीलर एक विशेष उपभोक्ता योजना और हर ट्रैक्टर खरीद पर एक सुनिश्चित उपहार भी दे रहे हैं।

राष्ट्रीय दलहन मिशन को मंजूरी

11,440 करोड़ रु. का बजट, लेकिन किसानों की मुनाफेदारी पर सवाल

(नई दिल्ली से निमेष गंगराडे)

नई दिल्ली (कृषक जगत)। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय दलहन मिशन को मंजूरी दे दी है। साथ ही, सरकार ने रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य- एमएसपी में भी वृद्धि की घोषणा की है। केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इस मिशन का उद्देश्य देश को दलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना, पोषण सुरक्षा को मजबूत करना और किसानों की आमदनी में वृद्धि करना है। सरकार ने वर्ष 2030-31 तक 35 मिलियन टन दलहन उत्पादन का लक्ष्य रखा है, जो 2024-25 में अनुमानित 24.2 मिलियन टन से लगभग 45 प्रतिशत अधिक है।

मिशन की रूपरेखा: 416 जिलों में लागू होगा, 100 प्रतिशत सरकारी खरीद की गारंटी राष्ट्रीय दलहन मिशन देश के 416 जिलों में लागू किया जाएगा। इसके तहत-

- धान की परती ज़मीनों का उपयोग
- उन्नत किस्मों के बीजों का प्रचार
- अंतरवर्तीय फसलें
- सूक्ष्म सिंचाई सहायता
- अरहर, उड़द व मसूर जैसी दालों की 100 प्रतिशत सरकारी खरीद जैसे कदम शामिल हैं।
- सरकार ने वर्ष 2025-26 के लिए रु. 11,440 करोड़ का बजट निर्धारित किया है।

किसानों की चुनौती: एमएसपी बढ़ा, पर लागत उससे तेज़।

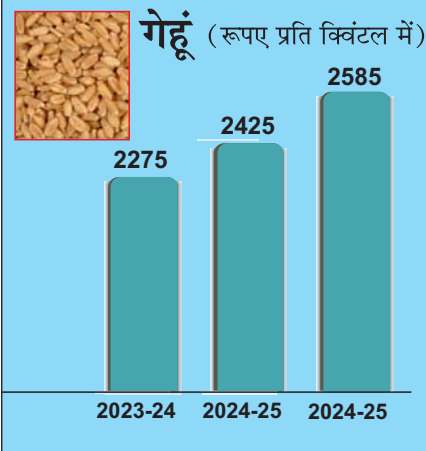
योजना आकर्षक दिखती है : एमएसपी में वृद्धि और सरकारी खरीद की गारंटी दोनों हैं।

लेकिन असली सवाल यह है कि क्या किसानों का मुनाफ़ा वाकई बढ़ेगा? विशेषज्ञों के अनुसार, दलहन खेती की लागत हर साल 8-12 प्रतिशत तक बढ़ रही है, जबकि इस बार एमएसपी वृद्धि केवल 4-6 प्रतिशत तक सीमित रही है। खाद, बीज, सूक्ष्म पोषक तत्व, सिंचाई और मशीनरी सभी में बढ़ती महंगाई ने किसानों

की लाभ मार्जिन को घटा दिया है।

एक कृषि अर्थशास्त्री के शब्दों में

- 'मुद्दा केवल एमएसपी बढ़ाने का नहीं है।
- असली समाधान तब मिलेगा जब उत्पादकता लागत से तेज़ बढ़े।



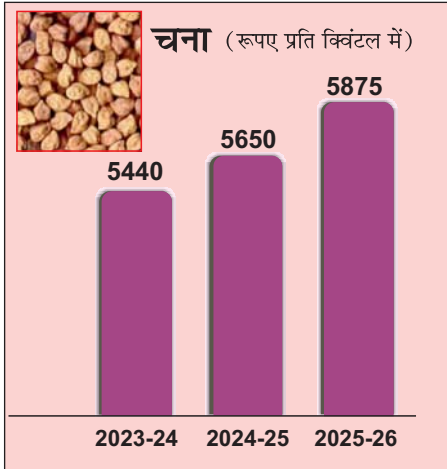
● जब तक बीज तकनीक, मशीनीकरण और लागत-कुशलता में सुधार नहीं होगा, दलहन मिशन किसानों की स्थायी आय को बचाए रखेगा और सब्सिडी योजना बनकर रह जाएगा।

तिलहन बनाम दलहन: नीति में असमान संतुलन

आंकड़े बताते हैं कि सरकार का झुकाव तिलहन और मोटे अनाजों की ओर अधिक है।

जैसे- सरसों और रेपसीड का एमएसपी 4.2 प्रतिशत, जबकि मसूर का केवल 4.48 प्रतिशत और चने का 3.98 प्रतिशत बढ़ाया गया है। वहीं कुसुम (सैफ़लॉवर) की एमएसपी वृद्धि 10 प्रतिशत से अधिक रही है। इससे सवाल उठता है कि अगर प्रोत्साहन बराबर नहीं, तो क्या सरकार दलहन उत्पादन का लक्ष्य हासिल कर पाएगी?

स्पष्ट है कि सबसे अधिक समर्थन तिलहन फसलों को मिला है, जबकि दलहन में वृद्धि सीमित रही।



एमएसपी वृद्धि तुलना (विपणन वर्ष 2025-26 बनाम 2026-27)

फसल	2025-26 (रु./क्विं.)	2026-27 (रु./क्विं.)	वृद्धि (रु.)	वृद्धि (प्रतिशत)
गेहूं	2,425	2,585	160	6.60
जौ	1,980	2,150	170	8.59
चना	5,650	5,875	225	3.98
मसूर	6,700	7,000	300	4.48
रेपसीड और सरसों	5,950	6,200	250	4.20
कुसुम (सैफ़लॉवर)	5,940	6,540	600	10.10



मिशन बढ़ा है, पर किसान की आय पर चिंता बरकरार

राष्ट्रीय दलहन मिशन निश्चित रूप से पोषण सुरक्षा और आयात घटाने की दिशा में बड़ा कदम है।

11,440 करोड़ रु. का बजट, ज़िला-स्तरीय कार्ययोजना और सरकारी खरीद की गारंटी - ये सभी कदम महत्वपूर्ण हैं। फिर भी किसानों की मूल समस्या बनी हुई है -लागत एमएसपी से तेज़ बढ़ रही है।

एमएसपी बढ़ने से किसानों को कुछ राहत जरूर है, लेकिन स्थायी लाभ तभी मिलेगा जब

उत्पादकता, तकनीक और सिंचाई दक्षता पर समान ध्यान दिया जाए।

दलहन मिशन की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि सरकार केवल 'कीमत और खरीद' तक सीमित न रहे, बल्कि बीज गुणवत्ता, अनुसंधान, लागत प्रबंधन और मूल्य स्थिरता पर समान रूप से ध्यान दे। तभी किसान को वास्तविक मुनाफ़ा मिलेगा और भारत सच में दलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर बन पाएगा।



सर्वोत्तम गुणवत्तावाली जैन ड्रिप की विस्तृत उत्पादन श्रृंखला - सभी फसलों* के लिए हर किसान के बजट के अनुरूप विभिन्न प्रकार के ड्रिप सिंचाई व्यवस्था के विकल्प स्टॉक में उपलब्ध हैं।

(# दलहन, धान, तिलहन, सब्जियाँ एवं फल बागानों आदि के लिए)

जैन टर्बो स्लिम - टीई व सुपर सेक्टर
5 से 20 मील (0.13 से 0.5 मिमी)
साईज - 12, 16, 20 मिमी



जैन टर्बो एक्सेल प्लस
0.4 मिमी, क्लास 1 एचडी व क्लास 2
साईज - 12, 16, 20 मिमी



जैन टर्बो लाईन सुपर
0.4 मिमी, क्लास 1 एचडी व क्लास 2
साईज - 12, 16, 20 मिमी साईज



जैन टर्बो लाईन - पीसी
क्लास 2
साईज - 16, 20 मिमी



जैन टर्बो टॉप - एचडी पीसी
१३, १५ मील (०.३३, ०.३८ मिमी) - क्लास 1 व 2
साईज - 12, 16, 20 मिमी



जैन पॉलीट्यूब एवं ड्रिपर्स
साईज - 12, 16, 20, 25, 32 मिमी



नोट : ड्रिपर्स व ड्रिपलाइन अलग-अलग प्रेशर रेटिंग में उपलब्ध

जैन ड्रिप
प्रति बीट, फसल भरपूर।

जैन इरिगेशन सिस्टम्स लि.
छोटे छोटे कबम, आसमान छूने का दम।

दूरभाष: 0257-2258011; 6600800
टोल फ्री : 1800 599 5000
ई-मेल: jisl@jains.com; वेबसाइट: www.jains.com



सावधान! नकल करके ड्रिप बनाने वाले एवं नकली ड्रिप कंपनियों और वितरकों से सतर्क रहें!